घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 253- मंगलवार 14- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

बद्रीनाथ मंदिर चंदा चोरी मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार

नई दिल्ली,13 जुलाई 2026। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं और चंदा चोरी के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में मुख्य आरोपी और मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को विशेष जांच दल ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात करीब 11 बजे आरोपी को राजधानी देहरादून के एक ठिकाने से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने उसे पूछताछ और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के दफ्तर में स्थानांतरित किया है। आरोपी को आज स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जहाँ से उसे आगे की कार्रवाई के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है। इस हाई-प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद से ही प्रमोद नौटियाल फरार चल रहा था। पुलिस की स्पेशल टीम लंबे समय से उसके संभावित छिपने के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने देहरादून में जाल बिछाया, जहाँ अंततः रविवार की रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले के कुछ ही दिन बाद बद्रीनाथ धाम में इस तरह की घटना का सामने आना देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस मामले ने न केवल मंदिर समिति बल्कि पूरे धार्मिक जगत को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद मंदिर की वित्तीय सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे को रखरखाव और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी हेराफेरी की गई थी। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब मंदिर प्रशासन को वित्तीय अनियमितता की भनक लगी और मामले में जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को 25 जून की एक महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी, जिसमें आरोपी प्रमोद नौटियाल नोटों की गड्डी ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहा है।

23 साल की कानूनी लड़ाई के बाद पिता को मिला इंसाफ...बेटी की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने 37 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश

मुंबई,13 जुलाई 2026। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे एक पिता के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 37 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने माना कि 12 वर्षीय बेटी को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 16 वर्षों तक कोमा में देखना और उसकी देखभाल करना किसी भी माता-पिता के लिए असहनीय पीड़ा है, जिसकी भरपाई धन से नहीं की जा सकती। मामला महाराष्ट्र के नासिक का है। वर्ष 2003 में 12 वर्षीय बच्ची ट्यूशन से साइकिल पर घर लौट रही थी, तभी एक तेज रफ्तार वैन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और कोमा में चली गई। इसके बाद वह करीब 16 वर्षों तक कोमा में रही। वर्ष 2019 में उसकी मृत्यु हो गई। इस दौरान बच्ची के पिता ने उसकी देखभाल में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इलाज, दवाइयों, अस्पतालों के चक्कर और घर पर विशेष देखभाल के कारण परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। इसी बीच बच्ची की मां का भी निधन हो गया, जिसके बाद बेटी की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारी अकेले पिता के कंधों पर आ गई। हादसे के बाद पिता ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) में चार लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने केवल 50 हजार रुपये का मुआवजा मंजूर किया। इस फैसले को चुनौती देते हुए पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई के दौरान पिता के वकील ने अदालत को बताया कि बच्ची की देखभाल पर प्रतिदिन लगभग 1,500 रुपये खर्च होते थे। इलाज, दवाइयों, मुंबई के अस्पतालों में चिकित्सा और पिता की नौकरी पर पड़े असर को देखते हुए उचित मुआवजा देने की मांग की गई। बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस ने दावा किया कि मांगी गई राशि अत्यधिक है, लेकिन न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है तथा 12 वर्षीय इकलौती बेटी को खोने का दर्द किसी भी कीमत में नहीं आंका जा सकता। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि 16 वर्षों तक कोमा में बेटी की हालत देखना माता-पिता के लिए असहनीय मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का विषय रहा होगा।

अमेरिकी कंपनी ने तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट के लिए एचएएल को 7वां इंजन सौंपा

नई दिल्ली,13 जुलाई 2026। भारतीय वायु सेना को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क-1ए का इंतजार लंबे समय से है। आपूर्ति की समय सीमा कई बार बदली जा चुकी हैं, लेकिन इस बीच अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 7वां इंजन सौंप दिया है, जिसे मालवाहक जहाज के जरिए यहां लाया जाएगा। इंजन को लेकर बुनियादी समस्याओं का समाधान होने के बाद अब विमान के उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है। भारतीय वायु सेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को कुल 180 एलसीए तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है। पहला समझौता फरवरी 2021 में एचएएल के साथ 48 हजार करोड़ का हुआ। इस अनुबंध में 73 तेजस मार्क-1ए जेट और 10 प्रशिक्षण विमान शामिल थे। रक्षा मंत्रालय ने 62,370 करोड़ रुपये का 25 सितंबर 2025 को 97 एलसीए मार्क-1ए लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए दूसरा ऑर्डर दिया, जिसमें 68 सिंगल सीटर और 29 ट्विन सीटर विमान हैं, जिनकी डिलीवरी 2027-28 में शुरू होकर छह वर्षों में पूरी होगी। भारतीय वायु सेना को 2024 में इंजन की पहली खेप मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस बीच कंपनी जीई एयरोस्पेस (जीई) ने एफ-404 इंजन का उत्पादन बंद कर दिया। भारतीय वायु सेना के साथ फरवरी, 2021 में अनुबंध होने के बाद एचएएल को इसी साल मार्च से तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करनी थी, लेकिन इसमें लगने वाले इंजन की अमेरिका से आपूर्ति में देरी की वजह से इंतजार लंबा हो गया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कंपनी ने 26 मार्च 2025 को पहला इंजन भारत को सौंपा। इसके बाद 13 जुलाई को जीई ने दूसरा इंजन भेजा। एचएएल को एलसीए मार्क-1ए के लिए तीसरा जीई-404 इंजन 11 सितंबर को मिला।

गो हत्या बैन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

कहा- इसमें सुधार की जरूरत,मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था...ये इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं

नई दिल्ली,13 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी दिन राज्य में गाय-बछड़ों के वध पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में सुधार की जरूरत है। राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि जब कानून तय श्रेणी की गायों के वध की अनुमति देता है, और उसके लिए निर्धारित स्थान भी तय हैं, तब अदालत का ऐसा निर्देश कानून के प्रावधानों के विपरीत है। इसे कायम नहीं रखा जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने आज इस मामले में नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

मद्रास हाईकोर्ट ने कुर्बानी रोकने को कहा था : मद्रास हाईकोर्ट ने 27 मई को (बकरीद से एक दिन पहले) तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में बकरीद या किसी अन्य दिन गाय और बछड़ों की कुर्बानी न हो। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की बेंच ने कहा- संविधान सभा की बहस में कहा गया था कि गाय भारत में पूजनीय मानी जाती है। भगवान कृष्ण के समय से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। कई मुस्लिम शासकों ने भी गोहत्या पर रोक लगाई थी। महात्मा गांधी भी गो संरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे।

हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला दिया था...

हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य सरकार को गाय,बछड़ों और दुधारू-पशुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। कोर्ट ने तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1958 की धारा-4 का उल्लेख किया। इसमें कहा गया है कि 10 साल से ज्यादा उम्र और प्रजनन के अयोग्य पशु को ही प्रमाणपत्र मिलने के बाद काटा जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान की सख्ती से व्याख्या होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी पशु की कुर्बानी दी जाती है तो वह केवल निर्धारित जगहों पर ही होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि संविधान सभा की बहस के दौरान भी इस बात पर जोर दिया गया था कि गाय भारतीय सभ्यता में पूजनीय रही है और भगवान कृष्ण के समय से उसका विशेष महत्व रहा है। यह जानकारी अदालत में दाखिल याचिका और न्यायिक आदेश के आधार पर सामने आई है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था-बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं

20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध संबंधी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता।

बंगाल में गुंडा दमन कानून लागू...बिना मुकदमे 365 दिन तक हिरासत का प्रावधान,बढ़ा राजनीतिक विवाद

नई दिल्ली,13 जुलाई 2026। पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने के उद्देश्य से आज से एक अत्यंत कठोर कानून लागू कर दिया गया है। विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार ने अपने पहले बड़े नीतिगत फैसले के रूप में 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026' को धरातल पर उतारा है। आम बोलचाल में इसे 'गुंडा दमन कानून' के नाम से जाना जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि यह कानून उन अपराधियों के लिए नजीर बनेगा, जो लंबे समय से प्रदेश की शांति व्यवस्था को बाधित कर रहे थे। इस कानून का मुख्य लक्ष्य समाज में भयमुक्त वातावरण बनाना और राज्य को अराजकता से मुक्त करना है।

बिना मुकदमे के 12 महीने की हिरासत और संपत्ति पर होगा एक्शन

इस नए कानून की सबसे चर्चित और सख्त धारा पुलिस को व्यापक अधिकार प्रदान करती है। अब पुलिस किसी भी संदिग्ध को बिना किसी औपचारिक चार्जशीट या लंबी अदालती प्रक्रिया के, एक वर्ष तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत होगी। यह प्रावधान उन अपराधियों पर

नकेल कसने के लिए है जो कानून की खामियों का लाभ उठाकर जमानत पर बाहर आ जाते थे। कानून में न केवल हिरासत का अधिकार दिया गया है, बल्कि अपराध के जरिए अर्जित की गई अवैध संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है। यदि दंगों या किसी भी असामाजिक गतिविधि के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी भरपाई के लिए अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने या उन पर बुलडोजर चलाने का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो गया है।

अपराधियों का होगा 'जिलाबदर', अपराध से पहले ही होगी गिरफ्तारी : सरकार द्वारा पारित इस कानून के तहत पुलिस के पास 'जिलाबदर' करने का भी पूर्ण अधिकार होगा। अब पुलिस आदतन अपराधियों और उपद्रवियों को चिन्हित कर उन्हें उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों या संबंधित जिलों से बाहर निकालने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा, इस कानून की एक बड़ी खासियत 'निवारक कार्रवाई' है,जिसके तहत पुलिस को अपराध या दंगे होने का अंदेशा होने पर संदिग्धों को घटना घटने से पहले ही हिरासत में लेने की शक्ति मिल गई है। बीते 29 जून को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित किया गया था, जिसे अब पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।

सरकार का दावा: लूटा हुआ पैसा अब आएगा जनता के काम

इस कानून की पैरवी करते हुए भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि राज्य में लंबे समय से व्याप्त गुंडागर्दी को समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान जिस तरह से अराजकता का बोलबाला था,उसे भाजपा सरकार ने अपनी सख्त नीतियों से काफी हद तक नियंत्रित किया है। सांसद ने स्पष्ट किया कि जिन अपराधियों ने जनता का पैसा लूटा है, उनसे वसूली की जाएगी और वह पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा। इस धन का उपयोग राज्य के विकास और आम जनता के कल्याणकारी कार्यों में किया जाएगा। सरकार का यह कदम राज्य में अपराध मुक्त समाज की दिशा में एक बड़ा और साहसी बदलाव माना जा रहा है।

उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर...100 से ज्यादा सड़कें बंद,भूस्खलन से बढ़ी मुश्किलें

देहरादून,13 जुलाई 2026। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। इसके कारण राज्य में दो राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 100 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। देहरादून में एक निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से एक महिला घायल हो गई,जबकि प्रेमनगर में बना अस्थायी पुल भी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है।

कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने देहरादून,उत्तरकाशी,चमोली,रुद्रप्रयाग,बागेश्वर, नैनीताल,चंपावत और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज गर्जना का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। यमुनोत्री और तवाघाट-गुंजी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मलबा हटाने का काम जारी है।

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में भी मौसम का असर

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के अवूरा क्षेत्र में बादल फटने से कई घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 120 से अधिक सड़कें बंद हैं। रोहतांग में हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। वहीं देश के कई अन्य हिस्सों में मानसून फिलहाल कमजोर बना हुआ है।

भारत में कतर के पूर्व अमीर खलीफा अल थानी के निधन पर शोक...नई दिल्ली केरल और मुंबई में आधा झुका तिरंगा

मुंबई,13 जुलाई 2026। महाराष्ट्र ने सोमवार को देश के अन्य राज्यों के साथ कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक मनाया। शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी का रविवार को निधन हो गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने सोमवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। महाराष्ट्र, केरल और नई दिल्ली से सामने आई तस्वीरों में कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी के निधन पर राष्ट्रपति भवन सहित विभिन्न सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ दिखाई दिया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। वहीं, मुंबई स्थित मंत्रालय तथा केरल के सरकारी भवनों पर

भी तिरंगा आधा झुकाकर श्रद्धांजलि दी गई। केरल के लिए यह शोक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राज्य का बड़ा प्रवासी समुदाय खाड़ी देशों से जुड़ा है और वहां के साथ उसके घनिष्ठ आर्थिक एवं जन-से-जन संबंध हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप केरल सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिन सरकारी भवनों और संस्थानों पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, वहां इसे आधा झुकाया जाए।

खान सर को मिली अग्रिम जमानत,राहत मिली...

नई दिल्ली,13 जुलाई 2026। पटना का बहुचर्चित मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद कानूनी मोड़ पर एक बड़े पड़ाव पर पहुंच गया है। पटना सिविल कोर्ट ने खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके चलते उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है। यह मामला 2 जून की रात मुसल्लहपुर इलाके में हुई मारपीट और फायरिंग से जुड़ा है। घटना के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें खान सर का नाम भी शामिल था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए यह फैसला लिया है। अदालत के इस फैसले से केवल खान सर ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगियों को भी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता पर गुवाहाटी कोर्ट का फैसला रद्द किया,कहा...जबरन कार्रवाई न हो

नई दिल्ली,13 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकता पर बड़ा फैसला देते हुए असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट के उन फैसलों को रद्द कर दिया, जिनमें 27 लोगों को विदेशी घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता और विदेशी दर्जे का निर्धारण निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया से होना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नागरिकता का मुद्दा संवैधानिक महत्व रखता है और इसे वैध प्रक्रिया के अलावा अन्य माध्यम से नहीं छीन सकते। लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, नागरिकता और विदेशी का दर्जा संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से उच्च महत्व का क्षेत्र है। अधिकारी किसी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर नागरिकता साबित करने का निर्देश

नहीं दे सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि संदेह का आधार बनने वाली सामग्री का खुलासा किए बिना नागरिकता साबित करने का भार किसी और पर नहीं डाला जा सकता। पीठ ने 27 व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक लगाई है। कोर्ट ने 27 अपीलकर्ताओं की अपील को स्वीकार करते हुए हुए उनके मामलों को नए सिरे से निर्णय के लिए संबंधित विदेशी न्यायाधिकरणों को वापस भेज दिया। हालांकि, कोर्ट ने भारतीय नागरिकता के अवैध दावों को रोकने में राज्य के हित को भी स्वीकार किया है। पीठ ने कहा, राज्य का यह सुनिश्चित करने में वैध हित है कि जो व्यक्ति नागरिकता का दावा करने के हकदार नहीं हैं, वे प्रक्रिया का दुरुपयोग करके ऐसी स्थिति प्राप्त न कर लें। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की स्थिति का निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए जो निष्पक्ष, वैध और उचित हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने भारतीय नागरिकता के लिए 27 अपीलकर्ताओं के दावों की खूबियों की जांच नहीं की है, इसलिए इनकी जांच संबंधित न्यायाधिकरण द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए। पीठ ने स्पष्ट किया कि पुनर्विचार का आदेश अपीलकर्ताओं के लिए न्यायसंगत राहत के रूप में न समझा जाए।

ज्ञानवापी,श्रीकृष्ण जन्मभूमि और संभल विवाद पर समझौते की कोशिश नाकाम,दोनों पक्षों ने किया इनकार

नई दिल्ली,13 जुलाई 2026। देश के चर्चित धार्मिक स्थलों-वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवादों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई मध्यस्थता की पहल को फिलहाल झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने इन जटिल मामलों को 'लोक अदालत' के माध्यम से बातचीत द्वारा सुलझाने का प्रस्ताव रखा था, ताकि आपसी सहमति से समाधान निकल सके। इसके लिए 21 से 23 अगस्त के बीच 'समाधान समारोह' आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के लंबित मुकदमों के निपटारे की योजना है। हालांकि, मंदिर और मस्जिद, दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। पक्षकारों का स्पष्ट मानना है कि इन मामलों में कानून के जटिल प्रश्न और ऐतिहासिक तथ्य शामिल हैं, जिन्हें केवल आपसी बातचीत से हल नहीं किया जा सकता, इसलिए कोर्ट में ही सुनवाई होना उचित है। ज्ञानवापी का मुद्दा वाराणसी स्थित परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर लंबे समय से अदालत में चल रहा है। हिंदू

पक्ष का दावा है कि 1993 तक इस परिसर के तहखाने में हिंदू प्रार्थनाएं की जाती थीं, जिसे सोमनाथ व्यास का परिवार नियमित रूप से करता था। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज करता है और परिसर पर मुस्लिम समुदाय के अनवरत अधिकार का तर्क देता है। मुख्य विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या औरंगजेब के काल में प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जैसा कि हिंदू पक्ष का आरोप है। इसके विपरीत, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल से भी पुरानी है और समय के साथ हुए बदलावों को मस्जिद का स्वरूप माना जाए।

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: ईदगाह की जगह पर मंदिर का दावा : मथुरा का विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और उससे सटी शाही ईदगाह मस्जिद की संरचना को लेकर है। हिंदू पक्ष ने दीवानी अदालत में याचिका दायर कर दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की पवित्र भूमि पर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और उनके भक्तों द्वारा दायर इस मुकदमे में मस्जिद को वहां से हटाने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष के अनुसार, स्थल पर ऐसे कई पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो उसे प्राचीन मंदिर होने का संकेत देते हैं। वर्ष 2020 में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का हवाला देते हुए एक दीवानी अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में मथुरा जिला अदालत में अपील के बाद इस फैसले को पलट दिया गया, जिससे यह कानूनी लड़ाई फिर से तेज हो गई है।

अयोध्या राम मंदिर दान प्रकरण... सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को जारी किया नोटिस,एसआईटी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली,13 जुलाई 2026। अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं, कोर्ट ने मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। ये याचिकाएं राजद सांसद सुधाकर सिंह, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी और वकील अजय कुमार राय व दिनेश कुमार यादव और हिन्दू धर्म परिषद ने दायर की हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक वकील ने कहा कि 123 साल की लड़ाई के बाद एक और लड़ाई शुरू हो गई है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप वाले सबूतों को सुरक्षित रखा जाना जरूरी है।

संपादकीय

ईंधन में आत्मनिर्भर बनाएगा एथनॉल

आजादी के बाद भारत में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं,जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी। हरित क्रांति ने हमें अनाज में आत्मनिर्भर बनाया। अब सरकार का एथनॉल कार्यक्रम का मकसद है ईंधन में आत्मनिर्भरता। भारत हर साल कच्चे तेल के आयात पर सात लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करता है। यह पैसा विदेश जाता है,हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है और हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। जब खाड़ी देशों में तनाव होता है,तब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं और उसकी मार सीधे आम भारतीय की जेब पर पड़ती है। सरकार का एथनॉल मिशन इसी निर्भरता को तोड़ने की कोशिश है। सरल शब्दों में कहें तो अपने गन्ने से,अपने खेतों से,अपना ईंधन बनाओ।

इसी दिशा में हाल में केंद्र सरकार ने 22 प्रतिशत,25 प्रतिशत,27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत एथनॉल मिले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी हटा दी। इसका सीधा मतलब है कि अब ज्यादा एथनॉल वाला पेट्रोल बनाना सस्ता होगा। इसके साथ सरकार ने 100 प्रतिशत एथनॉल को भी कानूनी मान्यता दे दी है। जब 2018 में यह योजना शुरू हुई थी,तब पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा पांच प्रतिशत से भी कम थी। 2023-24 में यह बढ़कर 15 प्रतिशत से अधिक हो गई। आज पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल (ई-20 ईंधन) मिलाया जा रहा है। ई-20 के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से सालाना करीब 30,000 करोड़ रुपये का आयात बिल कम होने का अनुमान है।

एथनॉल बनाने के लिए भारत के पास पर्याप्त संसाधन हैं। आज ज्यादातर एथनॉल गन्ने के शीरे और खराब या अतिरिक्त अनाज से बनाया जाता है,लेकिन भविष्य में इसके लिए और भी कई स्रोत उपलब्ध हैं। बांस,पराली,फसल कटाई के बाद खेतों में बचा हुआ अवशेष और नगरों से निकलने वाले कुछ प्रकार के कचरे से भी एथनॉल बनाया जा सकता है। इसे दूसरी पीढ़ी का एथनॉल कहा जाता है। इसके लिए खाने-पीने की फसलों का उपयोग नहीं होता,इसलिए खाद्य सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता। सरकार भी ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है, जिससे भविष्य में एथनॉल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिला है।

उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र और बिहार के गन्ना किसान लंबे समय से कम दाम और चीनी मिलों से भुगतान में देरी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे। एथनॉल योजना ने इस स्थिति को बदलना शुरू कर दिया है। अब सरकार की गारंटी के साथ डिस्टिलरी एथनॉल खरीदती है,जिससे चीनी मिलों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिला है। इसका लाभ किसानों तक भी पहुंच रहा है और उन्हें समय पर भुगतान मिल रहा है। पर्यावरण की बात करें तो एथनॉल मिश्रित पेट्रोल से धुआं कम निकलता है। गाड़ियों से निकलने वाले हानिकारक कण और कार्बन मोनोआक्साइड की मात्रा घटती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल भी जरूरी हैं, लेकिन उनके लिए बहुत पैसा और लंबा इंतजार चाहिए। एथनॉल सम्मिश्रण आज की गाड़ियों,आज के पेट्रोल पंपों और आज की खेती से काम करता है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।

अब सवाल उठता है,अगर एथनॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी तो आने वाली गाड़ियां कैसी होंगी? इसका जवाब है फ्लेक्स फ्यूल वाहन। ये गाड़ियां पेट्रोल, एथनॉल या दोनों के किसी भी मिश्रण पर चल सकती हैं। इनमें स्मार्ट इंजन होता है,जो खुद समझ लेता है कि टंकी में कौन सा ईंधन है और उसी हिसाब से काम करता है। यही फ्लेक्स फ्यूल की असली खूबी है। मारुति की वैगन-आर का फ्लेक्स फ्यूल माडल बाजार में आ चुका है। इसमें एथनॉल सेंसर,बेहतर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और जंग-रोधी पुर्जे लगे हैं,जो ज्यादा एथनॉल को झेल सकें। ई-20 को लेकर सबसे अधिक चर्चा माइलेज पर होती है। हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी स्वीकार किया कि एथनॉल का कैलोरी मान पेट्रोल से कम होने के कारण ई-20 ईंधन पर माइलेज में मामूली कमी आ सकती है। हालांकि यह प्रभाव सामान्य परिस्थितियों में सीमित रहता है और ई-20 के कारण वाहनों को भी किसी प्रकार की क्षति होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। फ्लेक्स-फ्यूल इंजनों के लिए किए गए परीक्षणों में भी माइलेज दक्षता पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पाया गया। अगर एथनॉल मिश्रित ईंधन पेट्रोल से 20-25 प्रतिशत सस्ता मिले तो क्या उसकी बचत कम माइलेज की कमी को पूरा नहीं कर देगी?

प्रकृति-पर्यावरण के सुरक्षा कवच को छेड़ों मत...
वर्ना विनाश से नहीं बच सकोगे

आत्माराम यादव
नर्मदापुरम,मध्यप्रदेश

सृष्टि की उत्पत्ति के साथ प्रकृति की आवाज का भी जन्म हुआ है। प्रकृति की यह आवाज प्रकृति तक ही सीमित नहीं है अपितु पूरी पृथ्वी के कण कण में समाहित है। प्रकृति की यह आवाज सकल ब्रह्मांड में,हर ग्रह-तारे एवं नक्षत्रों की अनंत सीमाओं में मौजूद है। प्रकृति की आवाज,प्रकृति से जुड़े प्रत्येक जीव व प्राणी के अंतस में है इसलिए इस प्रकृति से जुड़े वनस्पति,जीव आदि सभी प्राणी प्रकृति के साथ मित्रवत रहकर प्रकृति ओर खुद की,रक्षा कर रहे है। इसलिए इस धरा की प्रकृति मूलरूप से प्रत्येक जीव व प्राणी के लिये दया तथा रक्षा की आधारशिला है तथा प्रत्येक जीव,व्यक्ति तथा प्राणी के लिये सहिष्णुता व करूणा को प्रोत्साहित करती है,लेकिन मानव मात्र ने औद्योगिक विकास के नाम पर अनेक प्रकार का प्रदूषण पैदा कर प्रत्येक जीवन तथा वनस्पति जीवन की सुरक्षा कवच में सेंध मारकर खुद का जीवन कष्टमय किया है वही पर्यावरण को नष्ट करने का काम किया है ओर कर रहे है। पर्यावरण की महत्ता को पहचानने और प्रकृति के इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच को ओर अधिक शक्तिशली बनाने में अपना योगदान के लिए किसी कवि ने हमें आगाह किया है कि...

मत छेड़ों इस कुदरत को
तुम मिट्टी में मिल जाओगे।
खूब उगाओं पेड़ और पौधे,
गीत खुशी के गाओगे॥
जो फैलाए अधिक प्रदूषण
मानवता का दुश्मन है।
पर्यावरण की करें सुरक्षा
कुदरत उसका आंगन है॥
मत छेड़ों इस कुदरत को
तुम मिट्टी में मिल जाओगे।
खूब उगाओं पेड़ और पौधे,
गीत खुशी के गाओगे॥

पर्यावरण अर्थात प्रकृति का सुरक्षा कवच जिस प्रकार इंसान अपनी सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के सुरक्षा आवरण धारण करता है,ठीक उसी प्रकार प्रकृति ने न केवल स्वयं के लिये अपितु समस्त जीवों के लिये पर्यावरणरूपी आवरण धारण किया है किन्तु हमने अपने स्वार्थवश वायु जल,ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते प्रदूषण से वातावरण में मौसमी उथल-पुथल, तेजाबी बरसात,थर्राती धरती तथा जल स्तर कर गिरना मानव जीवन तथा सम्पूर्ण प्राणी जगत के लिये घातक बनाने का काम किया है। हम पर्यावरण के महत्व को साल में एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाकर औपचारिकता का निर्वहन करते है किन्तु शहरी,राज्यों, समूचे देश बल्कि सम्पूर्ण विश्व में अत्यधिक पर्यावरण प्रदूषण को घोषित कर अपनी मौत का मार्ग आसान बना रखा है। यही कारण है कि दुनिया में मानसिक तनाव,उच्च रक्तचाप,हृदय रोग,कैंसर,पेट की बीमारियां,आंत्रशोथ, एलर्जी,नपुंसकता या बांझपन,बहरापन तथा आँखों में जलन आदि सभी भयंकर बीमारियों का जन्मदाता प्रदूषित पर्यावरण पर चुप्पी साधे हुये है। टीबी.,कैंसर. एचआईवी तथा एड्स आदि जानलेवा बीमारियों का एकमात्र कारण केवल मात्र दूषित खान पान और पर्यावरण की कमी है। मनुष्य जब तक प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहेगा तो प्रकृति का तांडव भी तरोताजा बना रहेगा। कभी सूखा पड़ना,धरती का गर्माना,सामुद्रिक प्रकोप,अल्प वर्षा- बादलों के फटने से तबाह जल,जंगल,शहर आदि है,यह सब पर्यावरण असंतुलन का कारण है। जंगल कटान,नदियों से चौबीसों घंटे रेत,गिट्टी, मिट्टी आदि की लूटपाट है और इसी से पृथ्वी का असंतुलन बिगड़ा है,जिससे मनुष्य को भूकंप आदि के प्रकोप झेलने पड़ रहे है। इन सभी का समाधान है प्रकृति की आवाज,हरित क्रांती लाओ और अधिक से अधिक वृक्ष लगाओं। वृक्षा रोपण एक महान पवित्र कार्य है इसका महत्व भारत में प्राचीन काल से ऋषि मुनि मानते आते है तथा प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग मानते है। वायु जल,ध्वनि,इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते प्रदूषण से वातावरण में मौसमी उथल-पुथल, तेजाबी बरसात,थर्राती धरती तथा जल स्तर कर गिरना मानव जीवन तथा सम्पूर्ण प्राणी जगत के लिये घातक है।

एक दो घंटे की बरसात होने पर दिल्ली,मुंबई,कोलकाता,चेन्नई जैसे सेकड़ों शहरों में नगरपालिका-

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

महापालिका की लापरवाही से नालों की सफाई के अभाव में जीवन ठप्प पड़ जाता है,पूरा देश देखता रहता है की शहरों के मोहल्लों में लोगों के घरों में पानी किस प्रकार प्रवेश कर सब कुछ चौपट कर देता है। ये एक दिन की बात नहीं हर वर्ष मानसून के आते ही यह देशव्यापी पीड़ा का इंतजाम नहीं हो सका है। आज प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के लिये आवश्यक है कि वायुमण्डल में आक्सीजन व कार्बनडायआक्साइड का संतुलन बना रहे,आज की बढ़ती जनसँख्या के कारण जल,वायु इत्यादि समस्त प्राकृतिक संसाधनों की कमी सी होती जा रही है,आवश्यकता है कि हर मनुष्य अपने स्तर पर पृथ्वी को हरा-भरा रखने का प्रयास करें,जिस प्रकार बूंद-बूंद से एक घड़ा भर जाता है उसी प्रकार यदि प्रत्येक मनुष्य यदि अपने सम्पूर्ण जीवन में एक वृक्ष लगाने जैसा तथा एक वृक्ष को सुरक्षित रखने का महान कार्य कर पाता है तो वह इस प्रकृति पर बड़ा एहसान करता है, उसका यह छोटा सा प्रयास पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिये पर्याप्त होता है। डीजल-पेट्रोल व गैस जैसे ईंधनों से चलने वाले वाहनों से कार्बनडाय आक्साइड,सल्फर डाय आक्साइड, नाईट्रोजन कार्बनमोनो आक्साइड जैसी विषेली गैसे इन्डस्ट्रीज से निकलने वाला जहरीला प्रदूषण और ऊपर से ईंधन व अन्य सूक्ष्म लाभों के लिये मनुष्य हरे-भरे जंगलों को अंधा होकर काटता चला जा रहा है,परिणाम ये है कि प्रकृति का तापमान सामान्य से अधिक होता जा रहा है और बाढ़ सूखा,भूचाल जैसी अप्राकृतिक घटनायें इस प्रकार घटित होती है कि मानों प्रकृति अपना क्रोध प्रकट कर रही हो और लाखों करोड़ों की सँख्या में मनुष्य काल ग्रस्त हो जाते है,धरती पर आने वाले भयंकर भूचाल-भूकंप,उत्तराचंल में बर्फीले पहाड़ दरक रहे है,समूचा हिमालय बादल फटने से आने वाली बाढ़ की विभीषिका में विनाश पर विनाश किए जा रहा है जो प्रकृति से मानव की छेड़छाड़ का परिणाम मात्र की चेतावनी नहीं तो ओर क्या मानेंगें ? तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ का पिघलना,प्राकृतिक संसाधनों को एक सीमा से अधिक दोहन प्रकृति के साथ मनुष्य की छेड़छाड़ ही है और उसके भयंकर परिणामों की कल्पना मानव अपनी आँखों से साकार होते देख रहा है जहां घर के घर ही नहीं अपितु पूरा शहर धरशाही होकर कभी कीचड़ के दलदल में बहता दिखता है तो कभी जल में तबाह होते नजर आ रहा है ओर सरकारे लाचार होते हुये भी पीड़ित मानवों के लिए तत्काल पर्याप्त संसाधनों के अभाव आपदा के शांत होने की प्रतीक्षा करती दिखती है ओर जो तत्समय किया जाता है, वह न के बराबर ही होता है।

दिल्ली में बहने वाली यमुना इस अप्राकृतिक कृत्य का उदाहरण है, कभी गंगा-यमुना व सरस्वती अत्यन्त परम पूज्य नदियाँ भारत की शान हुआ करती थी परन्तु आज वहीं पवित्र पावन जमुना औधोगिक इकाइयों के प्रदूषण का केंद्र समस्त दिल्ली के प्रदूषित जल का संग्रहालय मात्र बन कर रह गयी हे,ये एक चेतावनी है मानवता को ये मात्र जमुना की नहीं अपितु विश्व की किसी भी प्राकृतिक जल संसाधन के लिये एक चुनौती हे जो नदिया न केवल सिंचाई का एकमात्र साधन बल्कि अनेक ऐसे कृत्यों का जैसे विद्युत उत्पादन,पेय व्यवस्था इत्यादि। धन्य है वो मानव जो कुदरत के ऐसे अनमोल खजाने पर न केवल लात मार रहा है बल्कि अपने लिये भयंकर त्रासदी के दरवाजे को दस्तक दे रहा है पर्यावरण से छेड़छाड़ का दूसरा उदाहरण है मध्य प्रदेश-गुजरात में बना इंदिरा सागर बांध परियोजना व टिहरी बांध परियोजना इस बांध के निर्माण मात्र के लिये मनुष्य ने करोड़ों अरबों वृक्षों की बलि चढ़ा दी है परन्तु उसे कल्पना भी नहीं है यदि पृथ्वी के इस भाग में यदि अप्राकृतिक घटना घटित हो गयी तो मानव के लिये महाविनाश होगा।

वन प्रकृति के लिये सुरक्षा कवच का ही नहीं अपूर्ति श्रृंगार का भी कार्य करते है। वन में हरे-भरे वृक्ष लतायें, झाड़ियाँ फल और फूल होते हे वे निवास स्थान होते है। भोरों,नाचती गाती तिलियाँ, पशु पक्षियों का मानव जाति की रक्षा करने वाली अमूल्य संपदा ये वन ही होते है। वृक्ष की महत्ता आदि काल से ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता में पूजनीय रही है कुछ वृक्ष जैसे नीम,पीपल,अशोक ये न केवल शुद्ध ऑक्सीजन का स्त्रोत है बल्कि ये वृक्ष सदियों से मानव जाति के लिये पूजनीय रहे हे। वृक्ष मूल रूप से मिट्टी के रक्षक है, वे न केवल आँधियों के तीव्र वेग को रोकते है वे मिट्टी को उड़ने से बचाते है। वृक्ष की जड़े पर्वतों की चट्टानों को मजबूती से पकड़े रहती है जिससे मिट्टी की सुरक्षा होती है और मिट्टी का वो उपजाऊ भाग जो ऊपरी परत के रूप में जाना जाता है संरक्षित रहता है। हवा की शुद्धता,शीतला इन्हीं पेड़ पौधों और वृक्ष होती है। वृक्ष ही वर्षा के होने या न होने के लिये जिम्मेदार है। जहाँ-जहाँ वृक्षों व वनों को असीमित रूप से काट दिया गया है वहां वर्षा होना ही रूक गयी है,ये वर्षा ही फसल के लिये आवश्यक है इससे मनुष्य जीवित रहता है। वातावरण की अस्वच्छ हवा को शुद्ध करने का काम भी प्रकृति के ये वन ही करते है,यदि निजी स्तर पर भी प्रत्येक व्यक्ति प्रदूषण कम करने पर कन्धे से कन्धा मिलाकर संकल्प ले ले कि वह न प्रदूषण फैलायेगा न ही किसी को फैलाने देगा तो पर्यावरण के लिये वरदान होगा ये संकल्प।

भारतीय वायु सेना की बढ़ती ताकत की
वैश्विक स्वीकृति है ग्लोबल एयर पॉवर रैंकिंग

दुर्गेश्वर राय
गोरखपुर,उत्तरप्रदेश

वैश्विक सैन्य पटल पर जब स्वतंत्र राष्ट्रीय वायु सेनाओं की तुलना की जाती है,तो भारतीय वायु सेना अमेरिका और रूस के ठीक पीछे दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायु शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ़ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट (डब्ल्यू.डी.एम.एम.ए.) की इस रिपोर्ट में भारत ने अपने चीन को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। 3,733 से अधिक सैन्य विमानों वाले चीन के विशाल बेड़े के मुकाबले भारत ने अपने 1,716 विमानों के साथ उच्च रेटिंग हासिल की है। यह वैश्विक मुकाम भारतीय वायुसेना के संतुलित बेड़े, लड़ाकू पायलटों के गहन प्रशिक्षण, और हालिया वर्षों में चलाए गए जटिल सामरिक अभियानों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस व्यापक मूल्यांकन को जारी करने वाली संस्था डब्ल्यू.डी.एम.एम.ए. एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय निकाय है,जो दुनिया के 103 देशों की 129 सैन्य हवाई सेवाओं और लगभग 48,000 विमानों के परिचालन डेटा की लगातार समीक्षा करती है। यह संस्था केवल किसी देश की वायुसेना की मुख्य शाखा का ही नहीं,बल्कि उसकी थल सेना, नौसेना और मरीन कोर के हवाई बेड़ों का भी अलग-अलग अध्ययन करती है। डब्ल्यू.डी.एम.एम.ए. का उद्देश्य केवल पारंपरिक हथियारों की गिनती से आगे बढ़कर आधुनिक युद्ध पद्धतियों के अनुरूप किसी देश की वास्तविक हवाई क्षमता को उजागर करना है।

वायु शक्ति के मापन के लिए यह संस्था अपनी विशेष टू वैल्यू रेटिंग (टी.वी.आर.) प्रणाली का उपयोग करती है। पारंपरिक धारणाओं से अलग, टी.वी.आर. फाइटर जेट्स की संख्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सैन्य बेड़े के समग्र संतुलन को मापती है। इसमें विमानों की तकनीकी स्थिति,आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं,लॉजिस्टिक्स समर्थन, प्रशिक्षण विमानों की उपलब्धता, रिफ्यूलिंग टैंकर्स,एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल

प्रणालियों और स्थानीय एयरोस्पेस निर्माण क्षमता का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। रक्षा आधुनिकीकरण की गति और भविष्य के नए ऑर्डर भी इस रेटिंग को प्रभावित करते हैं।

इस रेटिंग के मायने अंतरराष्ट्रीय रणनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। टी.वी.आर. का यह गणित साफ करता है कि युद्ध के मैदान में निष्क्रिय पड़े विमानों की भीड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण एक मुस्तैद, आधुनिक और बहुउद्देशीय बेड़ा होता है। यह रेटिंग दर्शाती है कि कोई देश किसी आपात स्थिति में अपनी सीमा से दूर कितनी तेज़ी से पहुँच सकता है और कितने लंबे समय तक हवा में अपना नियंत्रण कायम रख सकता है।

समग्र सैन्य हवाई शाखाओं की सूची में भारत 69.4 टी.वी.आर. अंक के साथ छठवें स्थान पर है,जहाँ शीर्ष पाँच में अमेरिका के चार अलग-अलग सैन्य अंग और रूसी वायुसेना शामिल हैं। परंतु केवल स्वतंत्र वायुसेनाओं की श्रेणी में आते ही भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ जाता है। भारत के 1,716 विमानों के बेड़े में 542 फाइटर जेट्स, 498 हेलीकॉप्टर,282 रणनीतिक परिवहन विमान और 374 प्रशिक्षण विमान शामिल हैं। राफेल,सुखोई-30 एमकेआई,मिराज-2000 और स्वदेशी तेजस जैसे उन्नत जेट्स भारत की हवाई सीमा की रक्षा करते हैं।

भारतीय वायुसेना की इस उच्च रेटिंग का बड़ा आधार उसके द्वारा चलाए गए बड़े और नवीन अभियान रहे हैं। बालाकोट एयरस्ट्राइक ने दुनिया को भारत की सटीक आक्रामक क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिचय दिया था। इसके बाद पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए तनाव के दौरान भारतीय वायुसेना ने जिस गति से अत्यधिक ऊंचाई वाले अग्रिम इलाकों में सुखोई-30,राफेल और थल सेना के भारी हथियारों की तैनाती की, उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सामरिक मुस्तैदी को साबित किया।

युद्धक अभियानों के अलावा,भारतीय वायुसेना ने संकटग्रस्त क्षेत्रों से मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में भी वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि यूक्रेन संकट के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत सी-17 ग्लोबमास्टर विमानों ने युद्धग्रस्त सीमावर्ती देशों से हजारों भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्वदेश पहुँचाया। इसी तरह सूडान से ऑपरेशन कावेरी और तुर्की-सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से राहत सामग्री और रेस्क्यू टीमों की त्वरित तैनाती ने भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की परिवहन क्षमता और मानवीय दृष्टिकोण को वैश्विक पटल पर रेखांकित किया है।

चलो लगाओ हिसाब

वीना तन्वी
नागपुर,महाराष्ट्र

क्या-क्या कहा ज़रा फिर से कहना
जब देखो तब बैठी रहती हो...?
यही कहा ना? तो चलो उठो उठाओ
कापी पेन जरा लिखो हिसाब गृहणी का
ये लेखिका दुनिया से आज कुछ कहती है।।
सुबह उठे गृहणी घर मे सबसे पहले क्या देखे
बर्तन,सामान फैलाएं यहां वहां घर मे रात मे
नित सबसे पहले उठा सफाई कर देती है।।
इस काम के बनते 500 महीना,नहीं लेती है
फिर बनाए नाश्ता बच्चों के लिए सुबह नित,
अलग-अलग फरमाईश पूरी बच्चों की करती है।।
बनते माह के 2500 रूपये,गृहणी नहीं लेती है
बच्चों को बार-बार उठाना कमरों में जाकर
टांगे दुःखती,दर्द सहती पर वो चुप ही रहती है।।
दोपहर रात का खाना मिला 6000 बाई लेती है
कपड़े धोना,सुखाना,प्रेस कर के जमा रखना
3000 होगा ही रेट अंदाज लगा गृहणी कहती है
आंगन को रोज़ झाड़ना सप्ताह मे दो बार धोना
बाई पड़ोसन की उससे 1200 रुपये लेती है।।
घर के चार बाथरूम धो,वाइपर से सुखाना
2400 रूपए, चुपचाप सब धो लेखिका सहती है
घर की झाड़-फूंक करना उसका रेट1500
महीना पड़ोसन अपनी बाई को हर माह देती है।।
किचन के रोज़ प्लेटफार्म को साफ करने के
400 रूपए बाईयों का रेट दिखा वीना कहती है।
बाजार जाकर राशन,सब्जी भाजी,फल लाना
गेहूं पिसाना,भारी बैग उठाना हिसाब लगाओ।।
लगाओ हिसाब शुरू से अब तक दावे से कहती
गृहणी की कमाई कमाऊं महिला से कम ना होती है।।
सब मिलाकर अगर मैं कहूं तो सच गृहणी की कमाई
20 से 25 हजार मासिक फिर भी मौन रह सहती है।।
मत सुनाओ,सताओ गृहणियों को कोई भी इतना
संस्कार की बेड़ी तोड़ लिख आज लेखिका कहती है।।

युद्धविराम का मिथक और वैश्विक शांति का संकट

संजीव ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच समय-समय पर घोषित होने वाले युद्धविराम और शांति प्रयासों ने विश्व समुदाय के सामने अनेक गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जब जब युद्धविराम की घोषणा हुई, कुछ ही समय बाद नए हमले,नई सैन्य कार्रवाइयाँ और नए आरोप सामने आ गए हैं। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि शांति केवल कूटनीतिक घोषणा बनकर रह गई है,जबकि ज़मीनी स्तर पर संघर्ष समाप्त होने के बजाय और जटिल होता जा रहा है। आज पूरा विश्व महँगाई,ऊर्जा संकट,आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता उसका प्रभाव तेल की कीमतों,खाद्यान्न,परिवहन,निवेश, रोजगार और आम नागरिक के जीवन तक पहुँचता है। यही कारण है कि मध्य-पूर्व का प्रत्येक तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

अमेरिका लंबे समय से इज़रायल का प्रमुख सहयोगी रहा है। उसके समर्थकों का तर्क है कि वह अपने सहयोगी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है,जबकि आलोचकों का मानना है कि अमेरिका के दोहरे मानदंड उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। दूसरी ओर इज़रायल का कहना है कि उसकी सैन्य कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है,जबकि उसके विरोधियों का आरोप है कि अत्यधिक सैन्य बल से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है। ईरान स्वयं को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता रहा है। अनेक पश्चिमी देश और कुछ क्षेत्रीय सरकारें आरोप लगाती रही हैं कि ईरान कुछ सशस्त्र संगठनों को समर्थन देता है,जबकि ईरान इन आरोपों से इनकार करता है और अपनी नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा क्षेत्रीय संतुलन का हिस्सा बताता है। यही परस्पर अविश्वास इस संघर्ष को और गहरा करता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनेक अवसरों पर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यदि ईरान वार्ता के लिए आगे आता है तो अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। इन दो संदेशों।कड़े सैन्य रुख और कूटनीतिक संवाद के बीच का विरोधाभास विश्व समुदाय को असमंजस में डालता है। इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार यह कहते रहे हैं कि इज़रायल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और आवश्यकता पड़ने पर हर खतरे का जवाब देगा।।उनके अनुसार ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताएँ इज़रायल के अस्तित्व के लिए चुनौती हैं।

दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई और ईरानी नेतृत्व बार-बार यह कहते रहे थे कि ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपनी संप्रभुता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा। ईरान यह भी आरोप लगाता है कि अमेरिका और इज़रायल क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। इन परस्पर विरोधी बयानों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि सभी पक्ष स्वयं को शांति का समर्थक बताते हैं,तो युद्ध की आग बार-बार क्यों भड़क उठती है? क्या युद्धविराम वास्तव में स्थायी शांति का माध्यम है, या केवल सैन्य और कूटनीतिक पुनर्संयोजन का अवसर? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने कई बार सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और तत्काल तनाव कम करने की अपील की है। उनका स्पष्ट मत रहा है कि मध्य-पूर्व किसी और युद्ध का भार नहीं उठा सकता। यह कथन केवल एक क्षेत्र की चिंता नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भविष्य की चेतावनी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महाशक्तियाँ शक्ति प्रदर्शन के बजाय विश्वास निर्माण को प्राथमिकता दें। इतिहास यह सिद्ध करता है कि युद्ध की राख से कभी स्थायी शांति नहीं जन्म लेती; स्थायी शांति केवल संवाद,पारस्परिक सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून के निष्पक्ष पालन से ही संभव है। इस प्रकार के संतुलित और सत्यापन योग्य उद्धरण आपके आलेख को अधिक विश्वसनीय और प्रकाशन-योग्य बनाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शांति वार्ताएँ अक्सर युद्ध की तैयारी के समानांतर चलती दिखाई देती हैं।

सुविचार

अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो।

महात्मा गांधी

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

सरगुजा में महिला एवं बाल विकास विभाग की भर्ती पर बड़ा सवाल...डाटा एंट्री ऑपरेटर पद का रहस्य अब भी बरकरार

भर्ती में पारदर्शिता या पर्दे के पीछे खेल? महिला एवं बाल विकास विभाग की चयन प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल

- **पिछले साल निरस्त,इस साल फिर भर्ती...आखिर डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर क्या है राज?**
- **महिला एवं बाल विकास विभाग की संविदा भर्ती में फिर विवाद,चयन प्रक्रिया पर उठे भाई-भतीजावाद के सवाल**
- **योग्यता बनाम सेटिंग! महिला एवं बाल विकास विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों का अविश्वास गहराया**
- **सरगुजा की संविदा भर्ती फिर सवालों के घेरे में...क्या प्रभावशाली लोगों के लिए बदले जा रहे हैं नियम?**
- **दावा-आपत्ति से पहले ही विवादों में भर्ती प्रक्रिया, महिला एवं बाल विकास विभाग से जवाब मांग रहे अभ्यर्थी**

-संवाददाता-
अंबिकापुर,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ का महिला एवं बाल विकास विभाग इन दिनों एक बार फिर संविदा भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है,मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के लिए जेंडर विशेषज्ञ,आईटी कोऑर्डिनेटर तथा पीएमएमवीवाई डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित तीन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही पुराने विवाद फिर चर्चा में आ गए हैं,विभाग ने पात्र-अपात्र सूची जारी कर 20 जुलाई तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की है, लेकिन इस प्रक्रिया के साथ सबसे बड़ा सवाल फिर वही खड़ा हो गया है– पिछले वर्ष डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद आखिर क्यों निरस्त किया गया था? यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर विभाग ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया। अब जब उसी पद पर दोबारा भर्ती हो रही है,तो अभ्यर्थियों और आम लोगों के बीच संदेह और गहरा गया है। बता दे की सरकारी भर्ती केवल नौकरी देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि शासन की विश्वसनीयता की परीक्षा होती है, यदि योग्य अभ्यर्थियों को यह विश्वास ही न रहे कि उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर अवसर मिलेगा, तो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के पास अभी भी अवसर है कि वह इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए,सभी अभिलेख सार्वजनिक करे और हर संदेह का तथ्यों के साथ उत्तर दे, अन्यथा यह भर्ती भी उन विवादित प्रक्रियाओं की सूची में शामिल हो सकती है, जिनकी चर्चा वर्षों तक होती रहती है, यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या अभ्यर्थी पर लगाए गए आरोपों के संबंध में उनका पक्ष उपलब्ध होता है, तो पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुसार उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

10 जुलाई 2026 को विभाग ने तीनों पदों के लिए पात्र-अपात्र सूची प्रकाशित कर दावा-आपत्ति आमंत्रित की, जेंडर विशेषज्ञ और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के आवेदकों की सूची,अंक और पात्रता संबंधी विवरण भी प्रकाशित किए गए हैं,लेकिन सूची जारी कर देना ही पारदर्शिता नहीं कहलाता,वास्तविक पारदर्शिता तब होगी जब विभाग बताए प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने अंक किस आधार पर दिए गए? अनुभव प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कैसे किया गया? किस अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करने का कारण क्या है? चयन समिति ने किस आधार पर निर्णय लिया?

क्या प्रभावशाली लोगों के लिए बदल जाते हैं नियम?- भर्ती प्रक्रिया को लेकर विभाग के भीतर और बाहर यह चर्चा है कि प्रभावशाली लोगों के परिजनों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है,इसलिए इन्हें आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसी आशंकाएं लगातार उठ रही हैं तो विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक जांच के लिए खोले।

क्या सरकारी नौकरियां अब मेरिट से नहीं...'मैनेजमेंट' से तय होंगी?

सरकारी भर्ती व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार होता है,निष्पक्षता,पारदर्शिता और योग्यता,लेकिन जब बार-बार शिकायतें सामने आने लगें,चयन प्रक्रियाएं विवादों में घिर जाएं और एक ही विभाग की संविदा नियुक्तियों पर लगातार प्रश्न उठने लगें,तब यह मान लेना कठिन हो जाता है कि सब कुछ सामान्य है,महिला एवं बाल विकास विभाग की संविदा नियुक्तियों को लेकर सरगुजा संभाग के कई जिलों सरगुजा,सूरजपुर,कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं,अभ्यर्थियों ने अनुभव प्रमाण-पत्र,मेरिट,चयन समिति और अंक निर्धारण को लेकर सवाल उठाए,लेकिन अधिकांश मामलों में जांच का परिणाम सार्वजनिक नहीं हुआ,यही कारण है कि अब हर नई भर्ती पर अभ्यर्थियों का भरोसा कमजोर होता जा रहा है।

डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद ही क्यों बना रहस्य?

यदि पिछले वर्ष किसी तकनीकी कारण से पद निरस्त किया गया था,तो आदेश सार्वजनिक होना चाहिए था, यदि किसी अभ्यर्थी की पात्रता विवादित थी, तो विभाग को बताना चाहिए था,यदि कोई शिकायत आई थी,तो उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए थी,यदि प्रक्रिया पूरी तरह सही थी, तो फिर केवल यही पद क्यों रोका गया जबकि अन्य पदों पर नियुक्तियां हो गईं? यही वह प्रश्न है जो पूरी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

अनुभव प्रमाण-पत्र सबसे कमजोर कड़ी?

संविदा भर्ती में अनुभव के अंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं,यदि अनुभव प्रमाण-पत्रों का वास्तविक सत्यापन नहीं होता, तो पूरी मेरिट सूची प्रभावित हो सकती है, क्या विभाग ने संबंधित संस्थानों से लिखित सत्यापन कराया? क्या वेतन भुगतान, उपस्थिति और सेवा अवधि का मिलान किया गया? क्या केवल कागज देखकर अंक दे दिए गए? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा,तब तक निष्पक्षता पर संदेह बना रहेगा।

दावा-आपत्ति केवल औपचारिकता न बन जाए...

आपत्ति प्रक्रिया का उद्देश्य केवल सूची प्रकाशित करना नहीं,बल्कि त्रुटियों को सुधारना है,यदि अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया,तो यह प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी।

चयन समिति भी जवाबदेह बने...

सरकारी भर्ती में चयन समिति केवल हस्ताक्षर करने वाली संस्था नहीं होती,उसी के निर्णय से तय होता है कि किसे नौकरी मिलेगी और कौन बाहर रहेगा,इसलिए चयन समिति की कार्यवाही,अंक निर्धारण और निर्णय प्रक्रिया भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

पूरे प्रदेश में एक जैसी शिकायतें– क्या यह केवल संयोग है?-

यदि अलग-अलग जिलों से एक जैसी शिकायतें सामने आती हैं, तो यह केवल संयोग नहीं माना जा सकता,सरकार को पूरे प्रदेश की संविदा नियुक्तियों का स्वतंत्र ऑडिट कराना चाहिए।

जनता के पैसे से चलने वाली भर्ती, जनता से क्यों छिपाई जाए?

सरकारी विभागों में होने वाली हर भर्ती जनता के पैसे से संचालित होती है,फिर मेरिट सूची,अंक, अनुभव सत्यापन और चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक करने में हिचक क्यों? यदि सब कुछ नियमों के अनुसार है तो पारदर्शिता से विभाग की विश्वसनीयता और बढ़ेगी।

सरकार से उठ रहे बड़े सवाल

- पिछले वर्ष डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद क्यों निरस्त हुआ?
- उस निर्णय का आदेश और कारण सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?
- क्या अनुभव प्रमाण-पत्रों का स्वतंत्र सत्यापन हुआ?
- क्या चयन समिति की कार्यवाही सार्वजनिक होगी?
- क्या सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिला?
- क्या शिकायतों की स्वतंत्र जांच होगी?

अब जांच से ही खत्म होगा विवाद

यदि सरकार वास्तव में पारदर्शी भर्ती व्यवस्था चाहती है तो केवल चयन सूची जारी करना पर्याप्त नहीं होगा,एक स्वतंत्र जांच समिति गठित कर निम्न बिंदुओं की जांच कराई जानी चाहिए पिछले वर्ष की भर्ती प्रक्रिया,डाटा एंट्री ऑपरेटर पद निरस्त करने का कारण,वर्तमान भर्ती में अंक निर्धारण, अनुभव प्रमाण-पत्रों का सत्यापन,चयन समिति की कार्यवाही,यदि कोई अनियमितता मिले तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही।

राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव की 93वीं जयंती पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि

टी.एस. सिंहदेव ने कहा...सरगुजा में कांग्रेस संगठन की मजबूत नींव रखने में राजमाता का रहा ऐतिहासिक योगदान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव की 93वीं जयंती सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उनके ज्येष्ठ पुत्र,पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं सरगुजा राजपरिवार के सदस्य टी.एस. सिंहदेव विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतीक्षा बस स्टैंड चौक स्थित स्वर्गीय महाराज एम.एस. सिंहदेव एवं राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव की युगल प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद मां महामाया मंदिर में पूजा-अर्चना की गई तथा श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने राजमाता के राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे दौर में कांग्रेस संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया, जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित थी। सत्तर और अस्सी के दशक में उन्होंने तत्कालीन अविभाजित सरगुजा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों का लगातार दौरा कर कांग्रेस की मजबूत संगठनात्मक नींव रखी। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का जन्म 13 जुलाई 1933 को हिमाचल प्रदेश के जुब्बल राजपरिवार में हुआ था। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं सरगुजा महाराज स्वर्गीय एम.एस. सिंहदेव से विवाह के बाद वे सरगुजा आईं और यहीं से सार्वजनिक जीवन एवं राजनीति की शुरुआत की। वे अंबिकापुर और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रहीं तथा अविभाजित मध्यप्रदेश में प्रकाशचंद्र सेठी और अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में आवास, पर्यावरण, मध्यम सिंचाई एवं वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वे सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रहीं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में डॉ. प्रेमसाय सिंह, जे.पी. श्रीवास्तव, शफी अहमद, राकेश गुप्ता, हेमंत सिन्हा, संजय विश्वकर्मा, मोहम्मद इस्लाम, विनय शर्मा, इंद्रजीत सिंह धंजल, जगन्नाथ कुशवाहा, दुर्गेश गुप्ता, मदन जायसवाल, शैलेंद्र प्रताप सिंह, फूलसाय लकड़ा, संजय सिंह, अनूप मेहता, लोकेश कुमार, आलोक सिंह, मेराज रंगरेज, जीवन यादव, विनोद एक्का, चंद्रप्रकाश सिंह, सोहन जायसवाल, सतीश बारी, बालकेश्वर तिर्की, कलीम अंसारी, आशीष जायसवाल, सरिता महंत, अविनाश कुमार, काजू खान, निखिल विश्वकर्मा, आलोक गुप्ता, रोशन कन्नौजिया, अंकित जायसवाल, वसीम अंसारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आशा से 'बुटन' तक 24 घंटे में पहुंची आबकारी टीम,लेकिन क्या अब भी बाकी है नशे के नेटवर्क की सबसे बड़ी कड़ी?

'सुपरमैन' रंजीत गुप्ता की एक और कार्रवाई...ब्रह्मपारा के कथित थोक विक्रेता राजेश मंदिलवार उर्फ बुटन गिरफ्तार,लगातार सफल दबिशों के बावजूद पूरे नेटवर्क पर उठते रहे सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

संभागीय आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन कहे जाने वाले रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ब्रह्मपारा से 28 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार की गई आशा पांडेय के मामले में आबकारी टीम ने 24 घंटे के भीतर उसके बताए कथित सप्लायर राजेश मंदिलवार उर्फ बुटन को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। आबकारी विभाग के अनुसार, 12 जुलाई को आशा

पांडेय की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने बताया कि उसने नशीले इंजेक्शन अपने ही मोहल्ले के निवासी राजेश मंदिलवार उर्फ बुटन से खरीदे थे। इसी जानकारी के आधार पर उसी शाम बुटन को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद 13 जुलाई को एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता का कहना है कि ब्रह्मपारा कभी ब्राउन शुगर की बिक्री के लिए बदनाम था और अब वहां कुछ लोग नशीले इंजेक्शनों के कारोबार में सक्रिय हो गए हैं। विभाग के अनुसार आशा पांडेय कथित रूप से फुटकर स्तर पर बिक्री करती थी, जबकि राजेश मंदिलवार उर्फ बुटन को थोक स्तर का विक्रेता मानते हुए कार्रवाई की गई है।

लगातार दूसरी नहीं,कईवीं बार सप्लायर तक पहुंची टीम : पिछले कुछ सप्ताह के दौरान आबकारी उड़नदस्ता ने कार्रवाई का एक समान पैटर्न अपनाया है। वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी के बाद मोशीम अंसारी तक पहुंचा गया। श्याम लॉज से साहिल तिर्की पकड़ा गया तो उसके बयान पर नितीश गुप्ता गिरफ्तार हुआ। सीतापुर में सजाद अली की गिरफ्तारी के बाद महबूब खान तक कार्रवाई पहुंची। अब आशा पांडेय के बयान के आधार पर राजेश मंदिलवार उर्फ बुटन को गिरफ्तार किया गया है। यह दर्शाता है कि टीम पूछताछ के आधार पर मामले की अगली कड़ी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

बढ़ती कार्रवाई,लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी : हाल के दिनों में आबकारी उड़नदस्ता ने नशीले इंजेक्शनों के अलावा हजारों नशीले कैप्सूल, महुआ शराब तथा अवैध शराब बिक्री के मामलों में भी कार्रवाई की है। इससे विभाग की सक्रियता दिखाई देती है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत मिलता है कि नशे का अवैध कारोबार अलग-अलग रूपों में मौजूद है। यही कारण है कि अब जनचर्चा केवल बरामदगी और गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। लोगों की अपेक्षा है कि जांच वहां तक पहुंचे जहां से यह पूरा नेटवर्क संचालित होता है, ताकि हर कुछ दिनों में नए आरोपी और नई खेप मिलने का सिलसिला वास्तव में थम सके।

फिर भी हर कार्रवाई के बाद सामने आ रहा नया नाम

इन लगातार सफल कार्रवाइयों के बावजूद एक प्रश्न लगातार बना हुआ है। यदि हर मामले में एक नया कथित सप्लायर सामने आ रहा है, तो क्या इसके ऊपर भी कोई बड़ी सप्लाई चेन सक्रिय है? अब तक इंजेक्शन, कैप्सूल और अन्य नशीली दवाओं के कई मामलों में स्थानीय विक्रेता और कथित सप्लायर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन तक माल पहुंचाने वाली बड़ी आपूर्ति श्रृंखला कहां से संचालित हो रही है।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन,अंबिकापुर में राजीव भवन से श्रीराम मंदिर तक निकाली आक्रोश रैली

टी.एस. सिंहदेव बोले...आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी और आर्थिक अनियमितताओं के मुद्दे को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने अंबिकापुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से स्थानीय श्रीराम मंदिर तक आक्रोश रैली निकालकर केंद्र सरकार,मंदिर ट्रस्ट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान मामले की निष्पक्ष जांच,दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी,ब्लॉक अध्यक्ष,मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल हुए। राजीव भवन से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्रीराम मंदिर पहुंची, जहां नेताओं ने सभा को संबोधित किया और मामले को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताया।

पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि यदि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो यह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था पर भी आघात है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की चोरी के लिए सीधे उन लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो मंदिर के प्रबंधन और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। उनका

कहना था कि धार्मिक संस्थाओं का संचालन पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और समाज के विश्वास के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिरों का प्रबंधन संत समाज और ऐसे स्वतंत्र लोगों के हाथों में होना चाहिए, जो श्रद्धालुओं के प्रति जवाबदेह हों। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि राम मंदिर निर्माण और चढ़ावे से जुड़े मामलों में सामने आए आरोपों ने देशभर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि जांच में वित्तीय अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि जांच एजेंसियां मंदिर से जुड़े सभी वित्तीय लेन-देन और अन्य निर्माण कार्यों की भी निष्पक्ष जांच करें ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राम केवल किसी एक संगठन या दल के नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक चेतना और करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। इसलिए राम मंदिर से जुड़े किसी भी वित्तीय विवाद की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है, जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए धार्मिक संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

मैनपाट में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत,पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी जांच

मायके पक्ष ने दहेज हत्या का लगाया आरोप,ससुराल पक्ष ने प्रताडऩा से किया इनकार...विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के मैनपाट विकासखंड के ग्राम कुनिया में एक 23 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। शनिवार शाम घर के भीतर महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद परिजनों ने उसे तत्काल नीचे उतारकर नर्मदापुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब मायके पक्ष ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज के लिए की गई हत्या बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं ससुराल वालों ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए इसे पारिवारिक विवाद के बाद उठाया गया कदम बताया है। अब पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। जानकारी के अनुसार ग्राम कुनिया निवासी मिनी यादव की शादी करीब तीन वर्ष पहले गांव के ही अनुज यादव से हुई थी। दंपती की 16 माह की एक बेटी भी है। शनिवार शाम घटना के समय पति अपनी बेटी को लेकर किराना दुकान गया हुआ था, जबकि घर में उसकी मां मौजूद थी। इसी दौरान महिला का शव घर की परछी में फांसी के फंदे पर लटका मिला। पति के लौटने के बाद परिजनों ने रस्सी काटकर शव नीचे उतारा और अस्पताल ले गए,लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर मृतका के मायके वाले भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शुरुआत से ही मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई। परिजनों का आरोप है कि शव पर

चोट के निशान थे,जिससे उन्हें विश्वास है कि पहले मारपीट की गई और बाद में घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मायके पक्ष ने नर्मदापुर में पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। इसके कारण रविवार को शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। सोमवार को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फोरेंसिक विशेषज्ञ, सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अब पुलिस को अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। मृतका के पिता संजय यादव का आरोप है कि शादी के बाद से उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। उनका कहना है कि विवाह में उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल दी थी और बाद में 50 डिसमिल जमीन भी बेटी के नाम कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष कार की मांग कर रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर पति, सास,ससुर और ननद द्वारा उसकी बेटी के साथ मारपीट की जाती थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बेटी को पिछले एक वर्ष से मायके आने नहीं दिया जा रहा था और रिश्तेदारों से मिलने तक पर रोक लगा दी गई थी। मृतका के भाई कुश यादव ने भी घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना वाले दिन शाम करीब चार बजे उनकी बहन से फोन पर बात हुई थी। उस समय उसने कोई परेशानी नहीं बताई। कुछ देर बाद विवाद की सूचना मिलने पर वह बहन के घर पहुंचा,लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। उसका दावा है कि घर के भीतर से मारपीट की आवाजें आ रही थीं। इसके बाद बहन की मौत की जानकारी मिली। भाई का आरोप है कि मारपीट के बाद हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया गया। वहीं ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि दहेज को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। उनके अनुसार घटना से पहले पति का नया मोबाइल फैंट की जेब में रह जाने के कारण धुल गया था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। उनका दावा है कि इसी विवाद के बाद महिला ने आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का।

घर के नौकर और ड्राइवर ने रची थी 5 लाख की चोरी की साजिश,खुद को बंधक बताकर किया गुमराह

गांधीनगर पुलिस और साइबर सेल ने चंद घंटों में किया खुलासा,विधि से संघर्षरत बालक सहित 4 आरोपी पकड़े गए...पूरी नकदी बरामद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

शहर के जवाहर मार्केट कॉलोनी स्थित एक व्यापारी के घर में हुई पांच लाख रुपये की चोरी का गांधीनगर पुलिस और साइबर सेल ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घर में काम करने वाले नौकर और ड्राइवर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी। घटना को अंजाम देने के बाद नौकर ने खुद के हाथ-पैर बांधकर अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी किए जाने की झूठी कहानी गढ़ दी। पुलिस ने विधि से संघर्षरत एक बालक समेत चार आरोपियों को पकड़कर चोरी की पूरी पांच लाख रुपये की नकदी और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार जवाहर मार्केट कॉलोनी निवासी सुभाष अग्रवाल 11 जुलाई को परिवार और मित्रों के साथ कोरबा के सतरंगा घूमने गए थे। घर की देखरेख के लिए उन्होंने अपने यहां काम

करने वाले ईश्वर यादव को छोड़ दिया था। रात करीब साढ़े तीन बजे पड़ोसी ने फोन कर बताया कि ईश्वर घबराया हुआ उनके घर पहुंचा है और कह रहा है कि कुछ लोग घर में घुसे, उसके हाथ-पैर बांध दिए और चोरी कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पड़ोसियों ने घर पहुंचकर देखा तो कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था और अलमारी खुली पड़ी थी। अगले दिन अंबिकापुर लौटने पर सुभाष अग्रवाल ने पाया कि तिजोरी में रखे पांच लाख रुपये गायब हैं। प्रारंभिक घबराहट में उन्होंने सोने के गहने चोरी होने की भी जानकारी दी, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि गहने उनकी पत्नी ने सुरक्षित दूसरी जगह रख दिए थे और केवल पांच लाख रुपये की नकदी चोरी हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर गांधीनगर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस को घर के नौकर और ड्राइवर की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पूछताछ में नौकर ईश्वर यादव और ड्राइवर संदीप कुमार साहू के बयान बदलने लगे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो पूरी साजिश सामने आ गई।

जांच में खुलासा हुआ कि ईश्वर यादव,ड्राइवर संदीप कुमार साहू, अनुराग दास और एक विधि से संघर्षरत बालक ने मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। सभी को पता था कि परिवार बाहर गया हुआ है। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने घर से पांच लाख रुपये निकाल लिए। चोरी के बाद संदेह से बचने के लिए ईश्वर यादव ने खुद के हाथ-पैर बांधकर अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी किए जाने की झूठी कहानी रची और पड़ोसियों को सूचना दी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने डाइट परिसर के पीछे बाउंड्रीवाल के पास छिपाकर रखा गया पांच लाख रुपये नकद बरामद कर लिया। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई होंडा साइन मोटरसाइकिल (सीजी-15-ईबी-0739) भी जब्त कर ली गई। पुलिस ने मामले में ईश्वर यादव (32), संदीप कुमार साहू (21),अनुराग दास (19) तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया है। विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड तथा तीनों वयस्क आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राम केवल किसी एक संगठन या दल के नहीं,बल्कि देश की सांस्कृतिक चेतना और करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। इसलिए राम मंदिर से जुड़े किसी भी वित्तीय विवाद की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है, जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए धार्मिक संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता,जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष,महिला कांग्रेस,युवा कांग्रेस,एनएसयूआई,सेवा दल सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

शासकीय हाई स्कूल डूमरडीह में शाला प्रवेशोत्सव एवं साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

शासकीय हाई स्कूल डूमरडीह में सोमवार को शाला प्रवेशोत्सव सह साइकिल वितरण कार्यक्रम हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह थीं। मुख्य अतिथि ने नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर आत्मीय स्वागत किया तथा उन्हें मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासित जीवन अपनाने और अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित किया। विद्यालय परिवार की ओर से कक्षा 9वीं के नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया गया तथा कक्षा 9वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वर्तमान कक्षा 10वीं के छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप कॉपी एवं पेन प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शासन की साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। अतिथियों ने इस योजना को छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने तथा विद्यालय तक उनकी सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत डूमरडीह की सरपंच श्रीमती

बैजन्ती देवी, उपसरपंच श्री बेचन यादव, पंच श्री इरफान खान,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री हीरा सिंह तथा श्री रमेश दास ने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व पर प्रेरक संबोधन दिया। विद्यालय के प्राचार्य श्री तनवीर अहमद ने विद्यालय परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण की आवश्यकता रखते हुए मांग प्रस्तुत की। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह ने बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए आवश्यक पहल करते हुए इसे पूर्ण कराने की बात कही। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक श्री देवप्रसाद,श्रीमती गुरप्रीत बक्शी,श्री कपूर सिंह पैकरा,श्री अजय खरे एवं श्री तुलसी कुमार धुर्वे का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता श्रीमती पूनम सिन्हा ने किया। अंत में सभी अतिथियों,जन प्रतिनिधियों एवं उपस्थितजनों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

राहत राशि और दोषसिद्धि दर की समीक्षा, लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

आईजी ने सोमवार को रेंज के सभी जिलों के डीएसपी (अजाक) की समीक्षा बैठक लेकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों, पीड़ितों को मिलने वाली राहत राशि और न्यायालयीन मामलों में दोषसिद्धि की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राहत राशि के मामलों का जल्द निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2024 में दर्ज 224 मामलों में 187 पीड़ितों को राहत राशि की पहली किस्त मिल चुकी है। वर्ष 2025 में दर्ज 319 मामलों में 228 तथा वर्ष 2026 में अब तक दर्ज 140 मामलों में 54 पीड़ितों को पहली किस्त का भुगतान किया गया है। आईजी ने चालान पेश होने और दोषसिद्धि के बाद मिलने वाली दूसरी व तीसरी किस्त के लंबित मामलों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा। बैठक में यह भी सामने आया कि कई मामलों में जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने अथवा जिला स्तरीय समिति में प्रकरण लंबित रहने के कारण राहत राशि के भुगतान में देरी हो रही है। इस पर आईजी ने पुलिस,जिला प्रशासन और आदिम जाति कल्याण विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आईजी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों में कम दोषसिद्धि दर पर चिंता जताई। उन्होंने दोषमुक्त मामलों का विश्लेषण कर विवेचना,साक्ष्य संकलन, गवाहों के मुकरने,चिकित्सकीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों तथा अभियोजन स्तर की कमियों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल समय-सीमा में विवेचना पूरी करना पर्याप्त नहीं,बल्कि उसकी गुणवत्ता भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने न्यायालय में लंबित महत्वपूर्ण मामलों की नियमित मॉनिटरिंग,गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा समीक्षा से मिले निष्कर्षों को भविष्य की विवेचना में लागू करने के निर्देश दिए।

सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में कर्नल राजेश बेंदा ने प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण किया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल राजेश बेंदा ने सोमवार को सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के प्रधानाचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। विद्यालय परिवार ने उनका स्वागत करते हुए उनके नेतृत्व में शिक्षा, अनुशासन एवं समग्र विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने का विश्वास व्यक्त किया। कर्नल राजेश बेंदा ने पंजाब आगरा, लेह-लद्दाख, असम, थेगू, कोलकाता, दीमापुर सहित अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर अपनी सेवाएं दी हैं।

उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2008 में दक्षिण-पश्चिमी कमान, 2017 में पूर्वी कमान तथा 2022 में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा चुका है।

एनआईएचएसएडी भोपाल के वैज्ञानिक कर रहे परीक्षण, सफल रहा ट्रायल तो सूकर पालकों को मिलेगा बड़ा लाभ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

शासकीय सुकर फार्म सकलो (अंबिकापुर) में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) वैक्सीन का ट्रायल मार्च से जारी है। यह भारत में इस वैक्सीन का पहला परीक्षण है,जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (एनआईएचएसएडी),भोपाल के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। फार्म प्रबंधक डॉ. अजय अग्रवाल ने बताया कि ट्रायल वैज्ञानिक मानकों के अनुसार किया जा रहा है। 8 जुलाई को एनआईएचएसएडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजू कुमार ने सकलो पहुंचकर ट्रायल की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान ब्लड, सीरम और नेजल सैंपल भी एकत्र किए गए। विशेषज्ञों के अनुसार अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूकरों में होने वाला अत्यंत घातक वायरल रोग है। यह घरेलू और जंगली दोनों प्रकार के सूकरों को प्रभावित करता है तथा इसकी मृत्यु दर काफी अधिक होती है। फिलहाल इस बीमारी का कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है और केवल लक्षणों के आधार पर सहायक उपचार ही दिया जाता है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सीके मिश्रा ने बताया कि ट्रायल जैव-सुरक्षा (बायो सिक्योरिटी) के सभी मानकों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा है। यदि यह परीक्षण सफल रहता है तो भविष्य में यह वैक्सीन भारत सहित अन्य देशों के सूकर पालकों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है ।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं राहुलदेव सिंह आ0रामवृक्ष सिंह उम्र-42 वर्ष निवासी डीसी रोड अम्बिकापुर पोस्ट एवं थाना अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ0ग0) 497001 उपरोक्त पते का निवासी है। यह कि मेरे पुत्र के नाम से जारी आधार कार्ड में उसका नाम शवरेय सिंह SHVRAY SINGH नाम दर्ज है जो त्रुटिवश दर्ज हो गया है। मेरे पुत्र का वास्तविक नाम जन्म प्रमाण पत्र में अनुकल्प सिंह ANUKALP SINGH दर्ज है जो सत्य एवं सही है। यह कि दोनो नामो में एकरूपता लाने में आवेदन छत्तीसगढ़ राजपत्र में नाम परिवर्तन करना चाहता हूँ जिसकी अनुमति माननीय महोदय से प्रदान करना चाहता है।

शपथग्रहिता
राहुल देव सिंह

नाम परिवर्तन सूचना

मैं अर्जुन साहू ARJUN SAHU आ. रामनारायण साहू, निवासी बिलासपुर चौक, वार्ड नं. 39, हनुमान मंदिर के पास, मणिपुर चौक, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छ0ग0 मेरा नाम अर्जुन साहू ARJUN SAHU है जो सत्य एवं सही है, उक्त नाम मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में दर्ज है जो सत्य एवं सही है।

मेरे आई.डी.बी.आई बैंक के बैंक खाता में मेरा नाम ARJUN PRASAD SAHU दर्ज है, जबकी मेरा वास्तविक नाम ARJUN SAHU है जिसे मैं अपनी उक्त बैंक खाता में सुधार कर दर्ज कराना चाहता हूं जिस हेतु स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं।

शपथग्रहिता
अर्जुन साहू

न्यायालय नायब तहसीलदार दरिमा जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26
दिनांक :-24/07/2026

ईश्तहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है - आवेदिका बुधियारो पति गंगा नाथ निवासी ग्राम करजी के द्वारा जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के धारा 13 (3) एवं छ0ग0 मृत्यु रजि0 नियम 2001 के नियम 09 (3) के अन्तर्गत अपने माता कुमारी प्रजापति पिता ईश्वर प्रजापति का मृत्यु दिनांक 15/02/2016 को ग्राम करजी में होना बतलाते हुये उनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय बावत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक 16/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील
नायब तहसीलदार
दरिमा,सरगुजा(छ0ग0)

14 जुलाई को होगा प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु का नेत्रोत्सव एवं नवयौवन दर्शन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा महोत्सव के अंतर्गत 14 जुलाई को प्रातः 4 बजे नेत्रोत्सव एवं नवयौवन दर्शन का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसी समय भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं माता सुभद्रा के नेत्रोत्सव पूजन के उपरांत श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। अनसर (विश्राम) काल पूर्ण होने के बाद भक्तों को भगवान के नवीन,तेजस्वी एवं दिव्य स्वरूप के प्रथम दर्शन का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त होगा। सनातन परंपरा के अनुसार स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु का महाअभिषेक होने के पश्चात उन्हें ज्वर (बीमार) आने की मान्यता है। इसके बाद वे लगभग पंद्रह दिनों तक अनसर गृह में विश्राम करते हैं, जहाँ उनके दर्शन सामान्य श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं। इस अवधि में पारंपरिक औषधीय सेवा एवं उपचार किया जाता है। स्वास्थ्य लाभ के उपरांत भगवान पुनः नवयौवन से युक्त दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।

न्यायालय नायब तहसीलदार,दरिमा जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

ईश्तहार पेशी दिनांकः-20/07/2026

रा.प्र.क्र./अ-6 अ/2025-26

ग्राम रेवापुर तहसील दरिमा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि, - आवेदक गोला राम आ0 रेचा निवासी ग्राम रेवापुर थाना व तहसील दरिमा के द्वारा ग्राम रेवापुर प0ह0न0 06 रा0नि0 मं0 सोहगा तहसील दरिमा में स्थित भूमि ख0न0 6/4, 11/4, 178/5, 177/4, 179/3, 217, 218/3, 219/4, 222/4 रकबा 0.041, 0.055, 0.039, 0.012, 0.172, 0.020, 0.020, 0.007, 0.004 0 भूमि बी-1 आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं किसान किताब की छाया प्रति संलग्न कर अपने आवेदन में बताया है कि, आवेदक के द्वारा आवेदित भूमि के राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम त्रुटीवश भोला राम दर्ज हो गया है। जबकि आवेदक अन्य दस्तावेज में गोला राम दर्ज है। उक्त त्रुटी को राजस्व अभिलेख में त्रुटी सुधार कर आवेदक अपना वास्तविक नाम गोला राम आ0 रेचा दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है

अतः उपरोक्त संबध मे जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं । नियत तिथि के उपरांत किसी भी का दावा/आपत्ति प्राप्त होने पर इस पर विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 02/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा द्वारा जारी ।

सील
ना0तहसीलदार
दरिमा,जिला-सरगुजा

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा-अम्बिकापुर

(कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर अम्बिकापुर)

/ / संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना / /

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर के परिसर में वाहन स्टैण्ड / फोटोकॉपी दुकान चलाने के इच्छुक एवं सक्षम निविदाकर्ता से बंद लिफाफा में शर्तानुसार निविदा निर्धारित प्रपत्र अनुसंलग्नक - ए में आमंत्रित है। वाहन स्टैण्ड / फोटोकॉपी दुकान संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्थान उक्त व्यवसाय संचालन हेतु निविदा के प्रारूप एवं शर्तों के विस्तृत जानकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड पर या जिला न्यायालय अम्बिकापुर के वेबसाईट - https://surguja.dcourts.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा जमा करने की प्रारंभिक तिथि -13.07.2026
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 23.07.2026
निविदा खोले जाने की तिथि - 24.07.2026
निविदा खोले जाने का स्थान -अध्यक्ष, संचालन समिति या वरिष्ठ न्यायाधीश जिला न्यायालय परिसर अम्बिकापुर।

सील
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा अम्बिकापुर छ0ग0

25 दिन बाद नौगई तिहरे हत्याकांड में

कोरिया पहुंची सीबीआई टीम

घटनास्थल, थाना और जब्त वाहनों का किया निरीक्षण

सीबीआई ने संभाली नौगई तिहरे हत्याकांड की कमान...25 दिन बाद कोरिया पहुंचकर शुरू की जांच

विधानसभा सत्र के पहले दिन नौगई हत्याकांड में बड़ी हलचल,कोरिया पहुंची सीबीआई टीम

अब सीबीआई के हाथों होगी नौगई हत्याकांड की पड़ताल,घटनास्थल से जुटाए शुरुआती साक्ष्य

नौगई तिहरे हत्याकांड : सीबीआई ने शुरू की पड़ताल,पुलिस विवेचना और साक्ष्यों की होगी नई समीक्षा

कोरिया पहुंची सीबीआई,नौगई तिहरे हत्याकांड की हर परत खंगालने की शुरू हुई कवायद

नौगई तिहरे हत्याकांड में नई शुरुआत, सीबीआई ने घटनास्थल और केस रिकॉर्ड का किया परीक्षण

25 दिन बाद सीबीआई की दस्तक, नौगई हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय एजेंसी के हाथों

नौगई तिहरे हत्याकांड : निष्पक्ष जांच की उम्मीदों के बीच कोरिया पहुंची सीबीआई,हर पहलू की होगी पड़ताल

-रवि सिंह-

कोरिया/सोनहत,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश के सबसे चर्चित और जघन्य नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच अब औपचारिक रूप से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के हाथों में पहुंच चुकी है,घटना के 25 दिन बाद और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को सीबीआई की छह सदस्यीय टीम कोरिया जिले पहुंची,टीम के जिले में पहुंचते ही इस बहुचर्चित मामले की जांच ने नया मोड़ ले लिया है,मृतकों के परिजन, स्थानीय नागरिक और पूरे प्रदेश की निगाहें अब इस बात पर टिक गई हैं कि क्या सीबीआई इस हत्याकांड की उन परतों तक पहुंच पाएगी, जिनकी मांग पीड़ित परिवार पिछले कई दिनों से करता आ रहा है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की टीम ट्रेन से कोरिया पहुंची,यहां पहुंचने के बाद टीम ने सबसे पहले चरचा कॉलरी स्थित विश्राम गृह (रेस्ट हाउस) में पहुंचकर कुछ समय विश्राम किया और प्रारंभिक तैयारियों के बाद सीधे नौगई गांव स्थित घटनास्थल के लिए रवाना हो गई, टीम के आगमन की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी सक्रिय हो गई थी,वहीं जिलेभर के मीडिया प्रतिनिधि भी सुबह से ही सीबीआई की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे।

केस डायरी और दस्तावेजों का किया परीक्षण-थाने में अधिकारियों ने मामले से संबंधित एफआईआर, केस डायरी,जब्ती पंचनामा,घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट, गवाहों के बयान, विवेचना से जुड़े दस्तावेज तथा अन्य रिकॉर्ड का प्रारंभिक परीक्षण किया,सूत्रों के अनुसार सीबीआई का पहला उद्देश्य यह जानना है कि घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने किस प्रकार जांच की, किन परिस्थितियों में कार्रवाई की गई और विवेचना किस दिशा में आगे बढ़ी।

घटनास्थल पर पहुंचकर समझा पूरा घटनाक्रम...

सीबीआई अधिकारियों ने सबसे पहले उस स्थान का विस्तृत निरीक्षण किया जहां 16 और 17 जून की दरमियानी रात जघन्य वारदात हुई थी,अधिकारियों ने घटनास्थल की भौगोलिक स्थिति, वाहनों की लोकेशन,संभावित आवाजाही के रास्ते तथा पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया,बताया जा रहा है कि टीम ने घटनास्थल पर काफी समय बिताया और वहां मौजूद परिस्थितियों का बारीकी से अध्ययन किया। माना जा रहा है कि सीबीआई वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र रूप से पुनर्समीक्षा करेगी।

सोनहत थाना पहुंचकर देखे जब्त वाहन और केस रिकॉर्ड

घटनास्थल के निरीक्षण के बाद सीबीआई की टीम सीधे सोनहत थाना पहुंची,यहां अधिकारियों ने इस प्रकरण में जब्त की गई जली हुई वाहन,अन्य क्षतिग्रस्त गाड़ियां तथा पुलिस द्वारा सुरक्षित रखे गए अन्य भौतिक साक्ष्यों का निरीक्षण किया, सीबीआई ने यह समझने का प्रयास किया कि स्थानीय पुलिस ने अब तक किन-किन साक्ष्यों को सुरक्षित रखा है, उनकी स्थिति क्या है और आगे की जांच में उनका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है।

विवेचना अधिकारियों से पूछे गए कई सवाल-प्रारंभिक जांच के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने उन पुलिस अधिकारियों और विवेचना अधिकारियों से भी चर्चा की जो अब तक इस मामले की जांच कर रहे थे,उनसे यह जानकारी ली गई कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कौन-कौन से कदम उठाए, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, किन साक्ष्यों को संकलित किया गया तथा किन बिंदुओं पर अभी जांच लंबित है,माना जा रहा है कि सीबीआई अभी पूरे प्रकरण को क्रमवार समझने का प्रयास कर रही है ताकि आगे की जांच वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाई जा सके।

मीडिया दिनभर करती रही जानकारी लेने का प्रयास-सीबीआई टीम के जिले में पहुंचने के बाद स्थानीय और क्षेत्रीय मीडिया की सक्रियता भी पूरे दिन बनी रही, मीडिया प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से बातचीत करने और जांच की दिशा जानने का प्रयास किया, लेकिन सीबीआई के अधिकारी पूरी तरह गोपनीयता बनाए रखते हुए किसी भी प्रकार की आधिकारिक टिप्पणी करने से बचते नजर आए,

पहले चरण में पुलिस अधिकारियों से होगी विस्तृत पूछताछ

जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में सीबीआई स्थानीय पुलिस अधिकारियों और उन कर्मचारियों से पूछताछ कर सकती है जिन्होंने घटना के बाद विवेचना की थी,सीबीआई यह समझना चाहेगी कि घटना से पहले पुलिस के पास क्या जानकारी थी? सूचना मिलने के बाद कितनी तेजी से कार्रवाई की गई? घटनास्थल पर पहुंचने में कितना समय लगा? किन परिस्थितियों में गिरफ्तारियां हुईं? कौन-कौन से वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए गए? किन बिंदुओं पर अभी जांच बाकी है? इन सभी पहलुओं के आधार पर आगे की जांच की दिशा तय की जाएगी।

सीबीआई की यही कार्यप्रणाली मानी जाती है कि वह प्रारंभिक जांच के दौरान सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं करती।

अब सीबीआई दर्ज करेगी अपना अलग मामला-सूत्रों के अनुसार अगला महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि सीबीआई इस प्रकरण को अपने यहां रेगुलर केस (आरसी) के रूप में दर्ज करेगी, इसके बाद इस मामले को सीबीआई का अलग केस नंबर मिलेगा और विवेचना पूरी तरह केंद्रीय एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी,इसके बाद जांच स्थानीय पुलिस की केस डायरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीबीआई अपने स्तर पर नए सिरे से साक्ष्य जुटाने,दस्तावेजों का परीक्षण करने और स्वतंत्र जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।

सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बन सकते हैं अहम आधार-मृतकों के परिजनों की लंबे समय से मांग रही है कि सीबीआई केवल प्रत्यक्ष आरोपियों तक सीमित न रहे बल्कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर),मोबाइल लोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा,डिजिटल साक्ष्य और संभावित संपर्कों की भी गहन जांच करे,परिजनों का मानना है कि घटना सुनियोजित थी और यदि सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है।

पुलिस की भूमिका भी जांच के घेरे में आने की उम्मीद- पीड़ित परिवार लगातार यह मांग करता रहा है कि केवल आरोपियों की भूमिका ही नहीं बल्कि घटना से पहले और बाद में स्थानीय पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए,परिजनों का कहना है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही,निर्णय संबंधी त्रुटि अथवा कर्तव्य निर्वहन में कमी रही है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए,अब जबकि सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है,ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि एजेंसी पूरे घटनाक्रम का निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी।

मृतकों के परिजनों को अब सीबीआई से न्याय की उम्मीद-घटना के बाद से लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे मृतकों और घायलों के परिजनों ने केंद्रीय एजेंसी के कोरिया पहुंचने पर संतोष व्यक्त किया है, उनका कहना है कि उन्हें विश्वास है कि अब जांच बिना किसी स्थानीय दबाव के आगे बढ़ेगी और हर पहलू की निष्पक्ष जांच होगी,परिजनों की मांग है कि इस मामले में केवल प्रत्यक्ष आरोपी ही नहीं बल्कि यदि किसी अन्य व्यक्ति, किसी प्रकार की साजिश,संरक्षण या लापरवाही की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

पूरे प्रदेश की निगाहें अब सीबीआई की अगली कार्रवाई पर-नौगई तिहरे हत्याकांड अब स्थानीय पुलिस की विवेचना से आगे बढ़कर देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों में शामिल सीबीआई के हाथों में पहुंच चुका है, पहले दिन के निरीक्षण और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आने वाले दिनों में गवाहों से पूछताछ, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच, घटनाक्रम का पुनर्निर्माण तथा संबंधित अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ की संभावना जताई जा रही है,जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और सीबीआई किन नए तथ्यों को सामने लाती है,इस पर केवल कोरिया जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं,अब पीड़ित परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई यह जांच उन्हें निष्पक्ष न्याय तक पहुंचाने का माध्यम बने।

घटती घटना | सरगुजा,सूरजपुर कोरिया समाचार | अम्बिकापुर सोमवार 13 जुलाई 2026 | 4

नौगई तिहरे हत्याकांड में बड़ा अपडेट....बैकुंठपुर पहुंच सकती है CBI की टीम,नए सिरे से होगी पूरे मामले की जांच : सूत्र

पीड़ित परिवार की सीबीआई जांच की मांग को मिल सकती है मंजूरी,पुलिस की शुरुआती जांच भी आ सकती है जांच के दायरे में...

नौगई तिहरे हत्याकांड में बड़ा अपडेट
बैकुंठपुर पहुंची सकती है सीबीआई की टीम
अब नए सिरे से होगी पूरे मामले की जांच: सूत्र
पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरिया बैकुंठपुर
CBI
नौगई हत्याकांड 16-17 जून की दरमियानी रात की घटना
पीड़ित परिवार की मांग होगी पूरी, पुलिस जांच के हर पहलू की होगी पड़ताल

निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार और पानी के छिड़काव नहीं होने से बढ़ी परेशानी, प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग

-संवाददाता-

बतौली,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बतौली-बगीचा राजकीय मार्ग की बदहाल स्थिति और सडक़ निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार से क्षेत्र के ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बारिश में सडक़ गड्ढों में तब्दील हो जाती है, जबकि धूप निकलते ही भारी वाहनों की आवाजाही से उडऩे वाली धूल लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है।

ग्रामीणों ने जल्द सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों के अनुसार बतौली से बगीचा तक करीब 16 किलोमीटर सडक़ निर्माण के लिए लगभग 33 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू होने के बावजूद अधिकांश स्थानों पर केवल पुरानी डामर सडक़ उखाडऩे और साइड शोल्डर की सफाई का काम ही हुआ है। इससे आवागमन और अधिक कठिन हो गया है। बतौली-बगीचा मार्ग के करीब दो किलोमीटर हिस्से की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। सडक़ पर बने गहरे गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कुछ समय पहले इसी मार्ग पर ट्यूशन पढऩे जा रहे एक छात्र की सडक़ हादसे में मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी सडक़ की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी नियमित रूप से पानी का छिडक़ाव नहीं करा रही है। भारी वाहनों के गुजरने के बाद सडक़ पर धूल का गुबार छा जाता है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रामीणों को स्वयं पाइप लगाकर सडक़ पर पानी डालना पड़ता है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग और प्रशासन से सडक़ निर्माण कार्य में तेजी लाने, नियमित जल छिडक़ाव कराने तथा जर्जर हिस्सों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

घर के सामने खड़ी बाइक चुराने वाले दो युवक गिरफ्तार,चंद घंटों में पुलिस ने बरामद की मोटरसाइकिल

वाड्रफनगर चौकी पुलिस की त्वरित कार्रवाई,दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

-संवाददाता-

बसंतपुर/बलरामपुर,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बसंतपुर थाना क्षेत्र के वाड्रफनगर में घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार वाड्रफनगर निवासी कैशर आलम ने 12 जुलाई को चौकी वाड्रफनगर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने 11 जुलाई की रात करीब 8 बजे अपनी मोटरसाइकिल घर के सामने खड़ी की थी। भोजन करने के बाद परिवार के साथ सो गए। देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच उठकर देखा तो मोटरसाइकिल गायब थी। काफी तलाश के बाद भी वाहन का पता नहीं चला, जिसके बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। प्रार्थी की शिकायत पर चौकी वाड्रफनगर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास जानकारी जुटाई और संदिग्धों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर दीपक प्रजापति (20 वर्ष) निवासी कुर्चीडांड, वाड्रफनगर तथा सुमीत कुमार पासवान (20 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक-5, वाड्रफनगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार कर लिया। उनकी निशानदेही पर चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक डाकेश्वर सिंह, सहायक उपनिरीक्षक रामजती राम, आरक्षक संतोष गुप्ता,शत्रुधन सिंह और विनोद कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में चोरी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

उर्वरक बिक्री में अनियमितता पर प्रशासन सख्त...5 दुकानों पर विक्रय पर प्रतिबंध,1 दुकान का लाइसेंस निरस्त की कार्यवाही,निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री करने पर 1 दुकान नोटिस जारी

-संवाददाता-

बलरामपुर,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

किसानों को उर्वरकों की निर्धारित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिले में उर्वरक दुकानों की सतत निगरानी एवं जांच की जा रही है। इसी कड़ी में कृषि विभाग एवं प्रशासन के संयुक्त टीम के द्वारा जिले के विकासखण्ड वाड्रफनगर व बलरामपुर में जांच के दौरान कुल 5 दुकानों में खाद बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा 1 दुकान को नोटिस जारी किया गया। साथ ही एक दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम पंडरी स्थित सुरेन्द्र खाद भण्डार दुकान के संबंध अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर दुकान की जांच की गई। जिसमें जांच में पाया गया कि दुकान संचालक के द्वारा खाद बिक्रय में अनियमितता बरती जा रही थी। जिस पर संयुक्त टीम के द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार वाड्रफनगर में जायसवाल फर्टिलाइजर्स में प्राप्त शिकायत के आधार पर कृषि विभाग एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय संबंधी शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में बताया कि निर्धारित मूल्य 532 रुपये के स्थान पर 600 रुपये लिए जाने की बात कही। जांच के दौरान दुकान से संबंधित बिल जांच दल द्वारा परीक्षण के लिए संज्ञान में लिया गया। मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए शिकायतकर्ता एवं दुकान संचालक, दोनों पक्षों के कथन दर्ज किए गए। प्रथम दृष्टया तथ्यों के परीक्षण के उपरांत कृषि विभाग द्वारा दुकान संचालक को मौके पर ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही संबंधित विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

कटकोना...सिर्फ एक कॉलरी नहीं,हजारों सपनों और यादों की जन्मभूमि

जहां बचपन ने सपने देखे और सफलता ने उड़ान भरी,वही है कटकोना

डॉ. सरिता झा की भावुक पोस्ट ने ताजा कर दी कटकोना की सुनहरी यादें...

कटकोना प्रकृति की गोद में बसा वह स्वर्ग,जो जीवनभर दिल में बस जाता है...

कोरिया का कटकोना,जहां की मिट्टी ने गढ़े डॉक्टर,इंजीनियर और हजारों सफल चेहरे...

बचपन,बरसात,पहाड़ और सरकारी क्वार्टर... कटकोना की यादों ने फिर कर दिया भावुक...

रोजगार ने बुलाया,यादों ने हमेशा के लिए अपना बना लिया...यही है कटकोना की पहचान...

कटकोना जहां हर पहाड़ी,हर बादल और हर रास्ता सुनाता है सफलता की कहानी...

स्वर्ग कहीं और नहीं,कटकोना की उन्हीं पहाड़ियों में था... डॉ. सरिता झा की पोस्ट ने छुए हजारों दिल...

बरसों बाद डॉ. सरिता झा की भावुक पोस्ट ने ताजा कर दी बचपन, प्रकृति और संघर्ष से सफलता तक की अनमोल यादें...

एसईसीएल की कोयला नगरी नहीं, हजारों परिवारों की भावनाओं का संसार है कटकोना,डॉ. सरिता झा की फेसबुक पोस्ट ने ताजा कर दी बचपन और सफलता की अनमोल यादें...

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कटकोना 13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। दुनिया में कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जिन्हें केवल नक्शे पर मौजूद एक गांव,कस्बा या कॉलोनी कह देना उनके साथ अन्याय होगा,वे स्थान लोगों के व्यक्तित्व,संस्कार,संघर्ष और सफलता की कहानी का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं,ऐसे स्थानों से लोग भले ही वर्षों पहले दूर चले जाएं,लेकिन उनकी स्मृतियां कभी दूर नहीं होतीं,छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कटकोना कॉलरी भी ऐसा ही एक स्थान है। कटकोना केवल एक कोलियरी क्षेत्र नहीं है, यह हजारों परिवारों के जीवन का वह अध्याय है,जहां बच्चों ने चलना सीखा, स्कूल जाना सीखा,सपने देखना सीखा और उन्हीं सपनों को पूरा करने की पहली उड़ान भी यहीं से भरी, यही कारण है कि जो व्यक्ति एक बार कटकोना में रहा,वह चाहे देश के किसी भी कोने में पहुंच जाए, उसकी यादों में कटकोना हमेशा जीवित रहता है,इन्हीं यादों को हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. सरिता झा ने अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से साझा किया, उन्होंने अपने बचपन के सरकारी क्वार्टर की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि कुछ जगहें केवल जगह नहीं होतीं,बल्कि हमारी पूरी दुनिया होती हैं,उनकी इस भावुक पोस्ट ने उन हजारों लोगों के दिलों को छू लिया,जिनका बचपन कभी कटकोना की पहाड़ियों,हरियाली और शांत वातावरण में बीता था।

कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होतीं- डॉ. सरिता झा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि वर्षों बाद जब उन्होंने अपने बचपन के उस सरकारी क्वार्टर की तस्वीर देखी तो ऐसा लगा जैसे पूरा बचपन आंखों के सामने जीवंत हो गया, उन्होंने लिखा कि कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होतीं,वे हमारी पूरी दुनिया होती हैं,उन्होंने आगे याद किया कि कैसे बरसात के दिनों में बादल घर की छत को छूते हुए निकल जाते थे, चारों ओर हरियाली रहती थी,ठंडी हवाएं,पक्षियों की चहचहाहट और प्रकृति का अनुपम सौंदर्य उनके जीवन का हिस्सा था,उस समय शायद उन्हें एहसास नहीं था कि वे धरती के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक में रह रही हैं,उन्होंने लिखा कि समय बदल गया, जीवन आगे बढ़ गया,लेकिन कटकोना की पहाड़ियां,वह सरकारी क्वार्टर और बचपन की यादें आज भी उतनी ही ताजा हैं,उनकी पोस्ट की अंतिम पंक्तियां सबसे अधिक भावुक कर देने वाली हैं कहते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर होता है, लेकिन मेरे लिए वह स्वर्ग कटकोना की उसी पहाड़ी पर बने छोटे से सरकारी क्वार्टर में था।

बिहार से आए पिता,लेकिन कर्मभूमि बनी कटकोना-डॉ. सरिता झा का पैतृक निवास बिहार के दरभंगा जिले में है, उनके पिता रामनरेश झा एसईसीएल में नौकरी के लिए वर्षों पहले कटकोना आए थे,सरकारी नौकरी के कारण पूरा परिवार कटकोना में आकर बस गया,यहीं बच्चों का जन्म हुआ,यहीं उनका बचपन बीता, यहीं परिवार ने जीवन के संघर्ष देखे,यहीं बच्चों ने सपनों को आकार देना शुरू किया,इस तरह भले ही पैतृक गांव बिहार रहा, लेकिन उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों कटकोना ही बन गई।

यहीं से शुरू हुई डॉक्टर बनने की यात्रा- डॉ. सरिता झा की शिक्षा भी कटकोना से ही शुरू हुई, उन्होंने प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई यहीं रहकर पूरी की, उस समय कटकोना जैसे छोटे क्षेत्र से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं था, आज इंटरनेट, कोचिंग और डिजिटल सुविधाओं का दौर है, लेकिन उस समय सीमित संसाधनों में पढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं था,फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी,वर्ष 2006 में उन्होंने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया पीएमटी परीक्षा उत्तीर्ण कर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, उस समय मेडिकल सीटें बेहद सीमित थीं, प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन होती थी,कोचिंग सुविधाएं आज जैसी उपलब्ध नहीं थीं, ऐसे समय में पहले ही प्रयास में चयन होना स्वयं में बड़ी उपलब्धि थी,आज वे एक सफल चिकित्सक हैं,लेकिन उनकी सफलता की बुनियाद कटकोना की उसी मिट्टी में रखी गई थी।

कटकोना ने केवल डॉक्टर ही नहीं, हजारों सपनों को जन्म दिया- कटकोना की पहचान केवल कोयला खदानों तक सीमित नहीं रही,यह क्षेत्र वर्षों तक शिक्षा,अनुशासन और सामुदायिक जीवन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता रहा,यहां रहने वाले अनेक परिवारों के बच्चे आज देश-विदेश में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंक अधिकारी,सेना के अधिकारी और निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं,उनकी सफलता की पहली सीढ़ी यही कटकोना रही।

पत्रकार की नजर से कटकोना- इस खबर से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी है, डॉ. सरिता झा के छोटे भाई अभिज्ञाय झा मेरे सहपाठी और घनिष्ठ मित्र रहे हैं, हमने एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ाई की, इसी कारण उनके घर आना-जाना लगा रहता था, उनके परिवार का सादगीपूर्ण जीवन, शिक्षा के प्रति समर्पण और बच्चों को आगे बढ़ाने की सोच आज भी याद है, जब सोशल मीडिया पर डॉ. सरिता झा की यह पोस्ट देखी तो लगा जैसे वर्षों पुरानी यादें फिर जीवित हो गई हों।

प्राकृतिक सुंदरता जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है- कटकोना की सबसे बड़ी पहचान उसका प्राकृतिक सौंदर्य है, बरसात के दिनों में यहां का दृश्य किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं दिखाई देता,घने जंगल...ऊंची पहाड़ियां...बादलों से ढकी सड़कें...ठंडी हवाएं... हरियाली से लदे पेड़...कल-कल बहते छोटे झरने...और प्रकृति की अद्भुत शांति,बैकुंठपुर से कटकोना तक का सफर ही अपने आप में एक पर्यटन अनुभव बन जाता है,जो व्यक्ति पहली बार यहां आता है,वह इसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता।

कटकोना केवल स्थान नहीं, एक भावना है-आज भले ही समय बदल गया है,नई पीढ़ी बड़े शहरों में बस रही है,पुराने सरकारी क्वार्टर बदल गए हैं,जीवनशैली बदल गई है,लेकिन कटकोना की पहचान आज भी वही है,यह स्थान लोगों के लिए केवल एक कॉलरी क्षेत्र नहीं,बल्कि जीवन के सबसे खूबसूरत वर्षों का प्रतीक है।

यादें कभी पुरानी नहीं होतीं-डॉ. सरिता झा की फेसबुक पोस्ट केवल एक व्यक्तिगत स्मृति नहीं है,बल्कि उन हजारों लोगों की सामूहिक भावना है जिन्होंने कभी कटकोना में जीवन बिताया, यह पोस्ट हमें यह भी याद दिलाती है कि सफलता केवल महानगरों की देन नहीं होती,कई बार छोटे कस्बे,शांत वातावरण,पारिवारिक संस्कार और प्रकृति की गोद ही बड़े सपनों की असली पाठशाला बन जाते हैं,कटकोना ऐसी ही एक पाठशाला है जहां से हजारों लोगों ने उड़ान भरी और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपनी पहचान बनाई,लेकिन उनकी सफलता की जड़ें आज भी उसी मिट्टी में हैं,जहां कभी बरसात के बादल उनके घरों की छतों को छूकर गुजरते थे,शायद इसलिए कहा जाता है कुछ जगहें कभी पीछे नहीं छूटतीं, वे हमेशा दिल में बस जाती हैं, कटकोना भी उन्हीं जगहों में से एक है।

रोजगार ने बुलाया,अपनापन रोक लेता था...

कटकोना में देश के विभिन्न राज्यों से लोग रोजगार की तलाश में आए,बिहार...उत्तर प्रदेश...झारखंड...पश्चिम बंगाल...ओडिशा...हर राज्य के लोग यहां एक परिवार की तरह रहते थे, बच्चे साथ पढ़ते थे, त्योहार साथ मनाए जाते थे, एक-दूसरे के सुख-दुख में पूरा कॉलोनी परिवार शामिल रहता था, यही कारण है कि नौकरी समाप्त होने के बाद भी लोग कटकोना को भूल नहीं पाए।

आज भी सोशल मीडिया जोड़ देता है पुरानी यादों से...

आज फेसबुक,व्हाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे ही कटकोना की कोई तस्वीर सामने आती है,यहां रह चुके लोग तुरंत अपनी यादें साझा करने लगते हैं,कोई अपने स्कूल को याद करता है,कोई खेल का मैदान, कोई पहाड़ियां,कोई सरकारी क्वार्टर,तो कोई बरसात के दिनों में बादलों के बीच बीता बचपन,यही किसी स्थान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वर्षों बाद भी लोग उसे उतने ही प्रेम से याद करें।

नजूल भूमि विवाद...पार्षद राजेश सोनी ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश

कहा...नया निर्माण नहीं,केवल 45 वर्ष पुरानी जर्जर दुकान की मरम्मत करा रहा हूं...

-संवाददाता-

पटना/कोरिया,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। नगर पंचायत पटना के वार्ड क्रमांक 09 में नजूल भूमि पर कथित अवैध निर्माण को लेकर सामने आए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है,सर्व आदिवासी समाज द्वारा एसडीएम बैकुंठपुर को शिकायत सौंपकर तत्काल जांच एवं कार्रवाई की मांग किए जाने के बाद अब मामले में वार्ड पार्षद राजेश सोनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी आरोपों को निराधार और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है। ज्ञात हो कि सर्व आदिवासी समाज ने शिकायत में आरोप लगाया है कि वार्ड क्रमांक 09 स्थित बाजारपारा क्षेत्र की नजूल भूमि पर कथित रूप से निर्माण कराया जा रहा है,संगठन ने प्रशासन से निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने,निष्पक्ष जांच कराने तथा आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है,शिकायत में यह भी कहा गया है कि यदि सरकारी अथवा नजूल भूमि पर बिना अनुमति निर्माण हो रहा है तो यह भविष्य में अतिक्रमण को बढ़ावा देगा और सार्वजनिक हित प्रभावित होगा,वहीं,इस पूरे मामले में पार्षद राजेश सोनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह असत्य, भ्रामक और उनकी छवि खराब करने की मंशा से लगाए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा न तो पटना बाजारपारा में और न ही किसी अन्य स्थान पर कोई नया भवन या दुकान का निर्माण कराया जा रहा है,राजेश सोनी ने बताया कि उनकी करीब 40 से 45 वर्ष पुरानी दुकान पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, दुकान की दीवारें और छत क्षतिग्रस्त हैं तथा कभी भी गिर सकती हैं,जिससे जनहानि और धनहानि की आशंका बनी हुई है,ऐसे में वे केवल अपनी पुरानी दुकान की मरम्मत करवा रहे हैं ताकि कोई दुर्घटना न हो, उन्होंने कहा कि 'मेरे द्वारा नजूल भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप पूरी तरह मिथ्या है। यह केवल मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास है।

मेरे खिलाफ यह सब राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जा रहा है,पार्षद ने यह भी कहा कि नगर पंचायत पटना में अनेक स्थानों पर वर्षों से अतिक्रमण मौजूद हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर केवल उनके मामले को ही विवाद का विषय बनाया जा रहा है,उनका कहना है कि यदि प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी है तो उसे सभी मामलों में समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए,न कि किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाया जाए,राजेश सोनी ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि जांच में यह सिद्ध हो जाए कि उन्होंने सरकारी या नजूल भूमि पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण किया है, तो वे कानून के अनुसार कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिना तथ्यों के लगाए जा रहे आरोप उचित नहीं हैं,अब इस पूरे मामले में प्रशासन की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, शिकायतकर्ताओं को उम्मीद है कि जांच के बाद यदि अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई होगी,वहीं पार्षद राजेश सोनी का कहना है कि निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी और यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे केवल अपनी पुरानी जर्जर दुकान की मरम्मत करा रहे हैं, कोई नया निर्माण या अतिक्रमण नहीं कर रहे।

माधुरी के गाने की वजह से हुई अनुराधा पौडवाल और अलका की दुश्मनी

सालों तक नहीं की बात; आज भी अनसुलझा है विवाद!

अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक के अनबन के किस्से 90 के दशक में एक गाने से शुरु हुए और जिस पर हाल ही में अनुराधा ने खुलकर बात की।

हिंदी सिनेमा में अक्सर दो सिंगर्स या एक्ट्रेस या फिर एक्टर्स के बीच अनबन के किस्से आज या कल से नहीं बल्कि सालों से सुनाई देते आ रहे हैं। 80-90 के दशक में में भी दो सिंगर्स ऐसी थीं,जिनमें अनबन के किस्सों ने खूब सुर्खियां बटोरीं और ये दोनों सिंगर्स कोई और नहीं बल्कि अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल हैं। अब खुलकर अनुराधा पौडवाल ने अपने उस किस्से की कहानी को बताया है...

अनुराधा-अलका में हुई थी अनबन

दरअसल अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल दोनों ही अपने वक्त की दिग्गज सिंगर रही हैं। दोनों ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गाने दिए हैं। हालांकि दोनों की लड़ाई असल में एक फिल्म के एक गाने से शुरु हुई थी। कहा जाता है कि आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म दिल वही फिल्म है जिसके चलते अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल के बीच राइवलरी

शुरु हो गई थी। हालांकि ये लड़ाई शुरु ऐसे ही नहीं हुई थी। फिल्म के गानों ने विवाद इतना खड़ा किया कि मामले में कई लोग बीच में आ गए थे,पर दिल फिल्म के चलते दोनों सिंगर्स क्यों झगड़ी थीं,तो इसके पीछे की वजह है कि अलका के गानों का हटा दिया जाना।

अलका के गानों को अनुराधा ने किया डब

दरअसल साल 1990 में आई दिल के गाने पहले अलका याग्निक ने गाए थे। अब क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन कुमार थे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के बाद अनुराधा पौडवाल ने उन्हीं गानों को अपनी आवाज में दोबारा डब किया। हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अनुराधा पौडवाल ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की।

दरअसल अनुराधा पौडवाल उस दौर में सिर्फ टी सीरीज की फिल्मों के ही गाने गाती थीं,क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था। ऐसे में गुलशन कुमार के कहने पर अनुराधा पौडवाल ने फिल्म के दो गानों को दोबारा से डब किया। बड़ी बात यह रही कि जो गाने पहले अलका फिल्म के लिए गा चुकी थीं,उन्हें दोबारा अनुराधा ने गाया और ये गाना बाद में अनुराधा की आवाज में हिट हो गए। खुद गुलशन कुमार ने अनुराधा के गाए गानों को प्रमोट किया।

आज भी अनसुलझा है विवाद?

फिल्म के गाना मुझे नींद ना आए काफी हिट हुआ। यह बात अलका को काफी बुरी लगी कि उनके गाए गानों को दोबारा से अनुराधा ने गाया है। यहां तक कि अलका की नाराजगी कुमार सानू और उदित नारायण से भी इसी मुद्दे को लेकर हुई थी।

1997 में फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू अलका याग्निक ने बताया कि पहली बार जब उन्होंने ऐसा होते देखा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरी बार फिल्म इतिहास में भी उनके साथ यही घटना हुई,जिसके बाद उन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर बोला कि उनके द्वारा गाए गानों को अनुराधा ने बिना उनकी जानकारी के डब किया और रिकॉर्ड किया।

कहा जाता है कि इस घटना के बाद अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक की ज्यादा बात नहीं हुई। आज भी दोनों सिंगर्स के बीच यह किस्सा अनसुलझा ही है। हालांकि हाल ही में इस पॉडकास्ट में अनुराधा ने इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है कि ऐसा उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के चलते किया है, यहांतक कि उन्होंने बताया कि उन्हें अलका के कुछ गाने बहुत अच्छे लगते हैं,जो उन्होंने गाए थे।

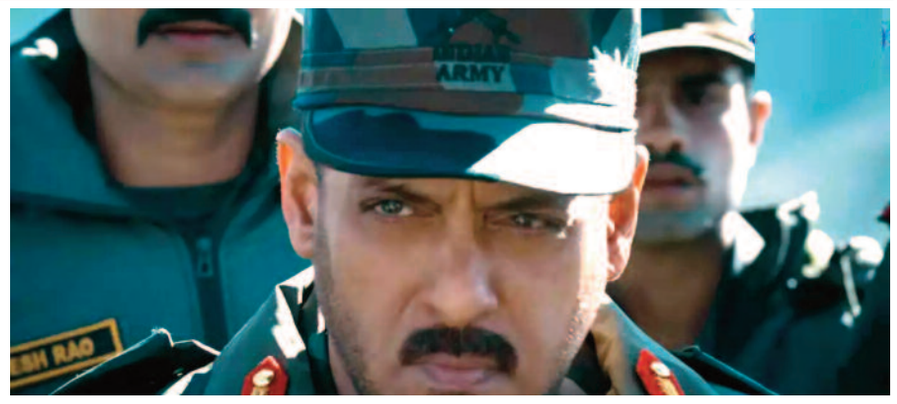

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज पर सस्पेंस, 2027 तक टलने की खबरों से बढ़ी चर्चा

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म मातृभूमि की रिलीज को लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू हो गई है। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को पहले इसी साल अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था,लेकिन बाद में इसकी रिलीज को टाल दिया गया। अब तक मेकर्स की ओर से फिल्म की नई रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि फिल्म को अगस्त में स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के मौके पर रिलीज किया जा सकता है। यह समय बॉक्स ऑफिस के लिहाज से काफी अहम माना जाता है,क्योंकि इस दौरान बड़ी फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद रहती है।

हालांकि,अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म की रिलीज 2027 तक भी आगे बढ़ सकती है। फिल्म का नाम पहले बैटल ऑफ गलवान बताया जा रहा था,लेकिन बाद में इसका टाइटल बदलकर मातृभूमि कर दिया गया। फिल्म की कहानी भारत-चीन सीमा पर गलवान घाटी की घटना से प्रेरित बताई जा रही है। हालांकि, फिल्म की कहानी और किरदारों को लेकर मेकर्स की ओर से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। एक ट्रेड सोर्स ने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि फिल्म से जुड़े कुछ मुद्दे अभी तक पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ये समस्याएं जल्द सुलझ भी जाती हैं तो भी फिल्म के लिए सही रिलीज स्लॉट ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है,क्योंकि आने वाले समय की कई बड़ी रिलीज डेट पहले ही अन्य फिल्मों ने बुक कर ली हैं। ट्रेड सोर्स के अनुसार,बॉलीवुड में कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़ी फिल्म की रिलीज डेट दूसरी फिल्म के साथ टकरा जाती है। हालांकि,सलमान खान इस मामले में अलग नजरिया रखते हैं। वह आमतौर पर किसी दूसरी फिल्म से बिना वजह टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कभी सलमान खान की फिल्म किसी अन्य बड़ी फिल्म के साथ रिलीज होती भी है तो वह पहले संबंधित फिल्म की टीम को इसकी जानकारी देना पसंद करते हैं। सलमान खान के इस रवैये को इंडस्ट्री में उनके सहयोगी व्यवहार के रूप में देखा जाता है।

बाथटब में सनी लियोनी का सिज़लिंग अवतार

तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

बॉलीवुड की बेबी डॉल सनी लियोनी जब भी स्क्रीन या सोशल मीडिया पर आती हैं,फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं,जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है।इन तस्वीरों में सनी लियोनी बाथटप में बैठकर हुस्न का जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं। सनी ने मल्टीकलर सिक्विन और क्रिस्टल वर्क वाला एक बेहद ग्लैमरस बॉडीसूट पहना हुआ है। पर्पल,पिंक,मरून और एक्वा ब्लू शेड्स के चेकर बोर्ड पैटर्न वाले इस आउटफिट में उनका टोंड फिगर साफ नजर आ रहा है।

इस सिजलिंग मोनोकिनी के साथ सनी लियोनी ने मैचिंग फिशनेट स्टॉकिंग्स कैरी किए हैं, जो उनके लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है। बाथटब में लेटकर और बैठकर दिए गए सनी के सेक्सी पोज किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी हैं।किसी तस्वीर में वह अपने हाथों को बालों में घुमाते हुए कैमरे को इंटेंस लुक दे रही हैं,तो किसी में वह अपनी आँखें बंद कर कातिलाना अदाएं बिखेर रही हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस में कॉन्फिडेंस और सेंसुअलिटी का बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा है। लुक को कम्प्लीट करने के लिए सनी ने बोल्ड रेड लिपस्टिक लगाई है,जो उनके चेहरे पर खूब फब रही है। स्मोकी आइज,परफेक्ट कॉन्टूरिंग और न्यूड मेकअप बेस के साथ उन्होंने कानों में बड़े गोल्डन हूप इयररिंग्स पहने हैं। सनी ने अपने बालों को खुला रखा है। सनी लियोनी की इन तस्वीरों ने यह साबित कर दिया है कि फैशन और बोल्डनेस के मामले में उनका मुकाबला करना आसान नहीं है। फैंस लगातार इन तस्वीरों पर फायर और हार्ट इमोजीस की बरसात कर रहे हैं।

आलिया भट्ट ने वेडिंग फंक्शन में पैपराज़ी को नहीं दिए पोज

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट अपनी सहजता और पैपराज़ी के साथ अच्छे व्यवहार के लिए जानी जाती हैं। आमतौर पर वह मीडिया कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए पोज देती हैं और फोटोग्राफर्स से बातचीत भी करती नजर आती हैं। हालांकि,हाल ही में हुए एक वेडिंग फंक्शन में उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला,जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया। आलिया भट्ट हाल ही में अभिनेत्री अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुई थीं। इसके अलावा वह अपनी करीबी दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर की शादी से जुड़े कार्यक्रमों में भी नजर आईं। शादी से पहले 10 जुलाई 2026 को आयोजित प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में आलिया ने शिरकत की थी।

इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आलिया भट्ट अपनी कार से उतरते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही वह वेन्यू पर पहुंचती हैं,वहां मौजूद पैपराज़ी उनकी तस्वीरें लेने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि,इस बार आलिया ने कैमरों के लिए रुककर पोज नहीं दिया और सीधे कार्यक्रम स्थल के अंदर चली गईं। वीडियो के मुताबिक,आलिया ने पैपराज़ी की तरफ देखा तक नहीं और बिना रुके अंदर चली गईं। आमतौर पर कैमरों के सामने सहज रहने वाली आलिया का यह अंदाज कुछ लोगों के लिए नया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके इस व्यवहार को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि,कार्यक्रम के अंदर से आलिया के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं। इन वीडियो में वह शादी समारोह का आनंद लेती और मेहमानों के साथ समय बिताती नजर आईं। फैंस को उनका यह अंदाज काफी पसंद आया। आलिया भट्ट और आकांक्षा रंजन कपूर की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों अक्सर एक-

दूसरे के साथ समय बिताते हुए नजर आती हैं। ऐसे में आलिया अपनी दोस्त के खास दिन का हिस्सा बनने पहुंची थीं। बता दें कि आलिया भट्ट बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं,जिनकी निजी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही सुर्खियों में रहती हैं। वह फिल्मों के साथ-साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए पलों को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। पैपराज़ी के साथ आलिया का रिश्ता हमेशा से ही सकारात्मक रहा है। वह कई मौकों पर फोटोग्राफर्स के साथ सहज बातचीत करती और तस्वीरें खिंचवाती दिखाई देती हैं। यही वजह है कि इस बार उनका कैमरों से दूरी बनाना लोगों के लिए खास चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं।

खेल समाचार

मेसी की चुनौती के लिए तैयार इंग्लैंड,पूर्व खिलाड़ी जो कोल ने जताया जीत का भरोसा

नई दिल्ली,13 जुलाई 2026। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर जो कोल का मानना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को रोकने में सफल रहेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अटलांटा स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम 21 साल में पहली बार अर्जेंटीना के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। इंग्लैंड और अर्जेंटीना की फुटबॉल प्रतिद्वंद्विता काफी पुरानी है। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक पांच बार आमने-सामने आ चुकी हैं। इनमें 1962,1966,1986, 1998 और 2002 के मुकाबले शामिल हैं। जापान में हुई पिछली भिड़ंत में इंग्लैंड ने डेविड बेकहम की पेनल्टी के दम पर अर्जेंटीना को हराया था। अर्जेंटीना मौजूदा विश्व चैंपियन है। टीम ने 2022 में कतर में वर्ल्ड कप खिताब जीता था। यह

अर्जेंटीना का तीसरा विश्व कप खिताब था और 36 साल बाद टीम को विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल हुआ था। हालांकि, जो कोल का मानना है कि इंग्लैंड की मजबूत आक्रमण क्षमता अर्जेंटीना के सामने बड़ी चुनौती साबित होगी।

2027 वर्ल्ड कप में रोहित-विराट पर बड़ा अपडेट

नई दिल्ली,13 जुलाई 2026। भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कप्तान शुभमन गिल ने बड़ा बयान दिया है। गिल ने साफ किया है कि दोनों अनुभवी खिलाड़ी 2027 वनडे विश्व कप की टीम योजना में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रोहित और विराट जैसे अनुभवी बल्लेबाजों की मौजूदगी टीम को मजबूती देती है और उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज से पहले कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की रणनीति और खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर बातचीत की। इस दौरान उनसे विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर सवाल किया गया। गिल ने कहा कि दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के अहम स्तंभ हैं और टीम की भविष्य की योजनाओं में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

विराट कोहली और रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम को कई यादगार जीत दिलाई हैं। 2023 वनडे विश्व कप में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। रोहित शर्मा ने कप्तान के तौर पर टीम को फाइनल तक पहुंचाया था,जबकि विराट कोहली टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल रहे थे। हालांकि, दोनों खिलाड़ियों की उम्र और लगातार बढ़ते क्रिकेट शेड्यूल को देखते हुए उनके भविष्य पर सवाल उठते रहे हैं। क्रिकेट प्रशंसक जानना चाहते हैं कि क्या विराट और रोहित 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक भारतीय टीम का हिस्सा बने रहेंगे। अब शुभमन गिल के बयान के बाद इस मुद्दे पर काफी हद तक स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है।

गिल ने कहा कि किसी भी टीम के लिए अनुभवी खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी होता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है और बड़े मुकाबलों में दबाव संभालने की क्षमता दिखाई है। ऐसे खिलाड़ियों का अनुभव टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। भारतीय टीम इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है,जहां कई युवा खिलाड़ियों को भी मौके दिए जा रहे हैं। शुभमन गिल खुद नई पीढ़ी के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल हैं और अब वह टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

वही तारीख,वही मैदान! दादा ने टी शर्ट उतारकर अंग्रेजों को दिखाया था आईना...

24 साल बाद भारतीय शेरनियों ने रचा इतिहास

13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स में सौरव गांगुली की कप्तानी में मिली ऐतिहासिक जीत के ठीक 24 साल बाद,इसी तारीख को भारतीय महिला टीम ने उसी मैदान पर इंग्लैंड को 270 रनों से करारी शिकस्त दी।

लंदन,13 जुलाई 2026। 13 जुलाई की तारीख भारतीय क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। ठीक 24 साल पहले इसी तारीख को साल 2002 में सौरव गांगुली की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड को धूल चटाई थी जिसके बाद गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट लहराकर इतिहास रच दिया था। अब 24 साल बाद उसी मैदान और उसी तारीख को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 270 रनों के विशाल अंतर से हराकर उस पुरानी याद को एक नए और ऐतिहासिक अंदाज में ताजा कर दिया है।

सौरव गांगुली ने लहरा दी थी टी शर्ट

13 जुलाई की यह तारीख भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक खास जज्बा जगाती है। आज से ठीक 24 साल पहले,इसी तारीख को साल 2002 में सौरव गांगुली की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। उस जीत के बाद दादा ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट लहराकर गोरे साहबों के घमंड को चकनाचूर किया था और भारतीय क्रिकेट को एक नया आक्रामक तेवर दिया था। अब 24 साल बाद, उसी ऐतिहासिक मैदान और उसी तारीख को भारतीय महिला टीम

ने इंग्लैंड को 270 रनों के विशाल अंतर से रौंदकर गांगुली के उस ऐतिहासिक पल को एक बार फिर जी उठा दिया है।

टीम इंडिया ने बनाया दबदबा

क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए इतिहास के इस पहले महिला टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 285 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। टीम को इस मजबूत स्थिति में पहुंचाने का श्रेय स्टार ओपनर स्मृति मंधाना को गया जिन्होंने 83 रनों की शानदार और संयमित पारी खेलकर भारतीय पारी की ठोस बुनियाद रखी।

क्रांति गौड़ ने मचाया तहलका

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों, खासकर तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। इंग्लैंड का मजबूत बैटिंग ऑर्डर भारतीय आक्रमण के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया और पूरी मेजबान टीम पहली पारी में महज 170 रनों पर ढेर हो गई। इस शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत को पहली पारी के आधार पर 115 रनों की बेहद महत्वपूर्ण और मजबूत बढ़त हासिल हुई जिसने मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया।

186 रन पर इंग्लैंड की टीम ऑलआउट

दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स के मैदान पर एक यादगार शतक जड़ा,जबकि स्मृति मंधाना ने एक बार फिर बल्ले का दम दिखाते हुए शानदार 70 रन बनाए। इन पारियों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने चौथी पारी में जीत के लिए एक असंभव सा लक्ष्य रखा। जवाब में रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम भारतीय स्पिन और पेस के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस गई और पूरी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 186 रन पर सिमट गई।

क्रांति गौड़ और यस्तिका का कमाल

इस मुकाबले में जीत के साथ ही भारत की यास्तिका भाटिया और क्रांति गौड़ ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो आज तक कोई महिला क्रिकेटर नहीं कर पाई थी। यास्तिका ने बल्ले से शतक ठोककर और क्रांति ने गेंद से कमाल दिखाकर लॉर्ड्स के ऐतिहासिक ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया।

विंबलडन फाइनल में केट मिडलटन की शानदार वापसी,चैंपियन जैनिक सिनर को सौंपी ट्रॉफी

विंबलडन,13 जुलाई 2026। एक और यादगार विंबलडन टूर्नामेंट के समापन के साथ जहां पूरी दुनिया की नजरें नए चैंपियन पर थीं,वहीं प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मेन्स सिंगल्स फाइनल के दौरान केट मिडलटन सेंटर कोर्ट में नजर आईं और उन्होंने विजेता खिलाड़ी जैनिक सिनर को प्रतिष्ठित विंबलडन ट्रॉफी प्रदान की।

केट मिडलटन की विंबलडन में वापसी को खास माना जा रहा है। वह इस साल के टूर्नामेंट में अपने परिवार के साथ आखिरी बार शामिल हुईं। उनके साथ प्रिंस विलियम,प्रिंस जॉर्ज और प्रिंसेस शार्लेट भी मौजूद रहे। शाही परिवार की मौजूदगी ने फाइनल मुकाबले की भव्यता को और बढ़ा दिया। केट मिडलटन हमेशा की तरह बेहद शानदार और आकर्षक अंदाज में नजर आईं। उनके पहनावे और व्यक्तित्व ने दर्शकों और मीडिया का ध्यान खींचा। उन्होंने सेंटर कोर्ट पर पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और विजेता को ट्रॉफी सौंपने की परंपरा निभाई। विंबलडन में केट मिडलटन की भूमिका केवल एक दर्शक की नहीं रही है। वह लंबे समय से ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब की संरक्षक भी हैं और हर साल टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण मुकाबलों में शामिल होती रही हैं। उनकी मौजूदगी को विंबलडन की परंपरा और प्रतिष्ठा का हिस्सा माना जाता है। मेन्स सिंगल्स फाइनल में जैनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। जीत के बाद जब उन्हें ट्रॉफी दी गई,उस दौरान केट मिडलटन ने मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई दी। यह पल कैमरों में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हुई। केट मिडलटन का विंबलडन से जुड़ाव लंबे समय से रहा है।

CMYK

आलोचना से उपलब्धि तक...स्वास्थ्य मंत्री के भरोसे पर लगी मुहर

5 मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी

जिसे लेकर उठे थे सवाल, उसी पर मिली सफलता, छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी की हरी झंडी

- आखिरकार पूरी हुई 'बाकी मैच' की पारी, प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी की स्वीकृति
- स्वास्थ्य मंत्री बोले थे... 'अभी मैच बाकी हैं',अब एनएमसी की मंजूरी के साथ पूरा हुआ वादा
- प्रदेश को मिली बड़ी सौगात : एनएमसी ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों को दी मंजूरी,बढ़ेंगी एमबीबीएस सीटें
- आलोचनाओं का जवाब उपलब्धि से,छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी

न्यूज डेस्क

रायपुर,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। आखिरकार वह इंतजार खत्म हो गया, जिसका प्रदेश के लाखों लोगों, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को लंबे समय से इंतजार था, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के पांच नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संचालन की स्वीकृति प्रदान कर दी है, इसके साथ ही प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है, यह स्वीकृति केवल नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत भर नहीं है, बल्कि प्रदेश के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं,विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और मेडिकल शिक्षा के नए अवसरों का द्वार भी खोलती है।

एक महीने पहले तक हो रही थी तीखी आलोचना- करीब एक महीने पहले तक हालात बिल्कुल अलग थे,मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति में हो रही देरी को लेकर सरकार,विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल,विपक्ष, मीडिया और सोशल मीडिया के निशाने पर थे,कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं कि इस सत्र में मेडिकल कॉलेजों को अनुमति नहीं मिल पाएगी, सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतनी तैयारी के बावजूद स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था और इसे स्वास्थ्य विभाग की विफलता के रूप में प्रस्तुत कर रहा था।

स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं छोड़ा भरोसा-इन सबके बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लगातार यह विश्वास दिलाते रहे कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी अवश्य मिलेगी,उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर कहा था 'मेडिकल कॉलेज बनकर रहेगा...अभी मैच बाकी है, उस समय उनके इस बयान पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं,कुछ लोगों ने इसे केवल राजनीतिक बयान माना,लेकिन स्वास्थ्य मंत्री लगातार अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कमियों को दूर कराने और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के समक्ष आवश्यक दस्तावेज एवं व्यवस्थाएं पूरी कराने में जुटे रहे।

अब सच साबित हुआ भरोसा

अब जब राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने पांचों मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान कर दी है, तो स्वास्थ्य मंत्री का वह भरोसा सही साबित हुआ है, जिस 'बाकी मैच' की बात उन्होंने कही थी, वह अब पूरा हो चुका है, यह उपलब्धि केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों नागरिकों, मेडिकल छात्रों और भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी है।

प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मिलेगी नई मजबूती

नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने से प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ेगी, इससे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों का रुख कम करना पड़ेगा,वहीं मेडिकल कॉलेजों के साथ विकसित होने वाले अस्पतालों से स्थानीय लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं भी अपने जिले में ही उपलब्ध होंगी, विशेष रूप से आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा,मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ,पैरामेडिकल कर्मचारियों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी होगा।

शांत कार्यशैली,परिणाम पर विश्वास

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की कार्यशैली को करीब से जानने वाले लोग मानते हैं कि वे बिना अनावश्यक बयानबाजी के काम करने में विश्वास रखते हैं,पिछले दो दशकों से सार्वजनिक जीवन में उनकी पहचान ऐसे जनप्रतिनिधि की रही है जो विकास कार्यों को लेकर दृढ़ रहते हैं और परिणाम आने तक प्रयास जारी रखते हैं, मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति का यह पूरा घटनाक्रम भी उसी कार्यशैली का उदाहरण माना जा रहा है,जब आलोचनाएं अपने चरम पर थीं,तब भी उन्होंने संयम नहीं खोया और लगातार यही कहा कि मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी मिलेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य के लिए बड़ा कदम

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की यह मंजूरी प्रदेश की स्वास्थ्य नीति के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले वर्षों में इससे प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, चिकित्सा शिक्षा को मजबूती मिलेगी और जिला स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित होंगी।

आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा, परिणाम सबसे बड़ा जवाब

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और मंत्रियों की जवाबदेही तय होती है, इसलिए आलोचना होना भी स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी योजना या परियोजना का वास्तविक मूल्यांकन उसके अंतिम परिणाम से होता है,नए मेडिकल कॉलेजों को मिली स्वीकृति यह दर्शाती है कि लगातार प्रयास और प्रशासनिक समन्वय से जटिल प्रक्रियाओं को भी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है, प्रदेश के लोगों के लिए यह केवल एक प्रशासनिक मंजूरी नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं,चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है,अब यह कहा जा सकता है कि जिस 'मैच' के बाकी होने की बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही थी,वह पूरा हो चुका है और उसका परिणाम प्रदेश के हित में सामने आया है।

पिंक ई-रिक्शा से विधानसभा पहुंचे मंत्री और विधायक,महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश

रायपुर,13 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और विधायक ललित चंद्राकर पिंक ई-रिक्शा से विधानसभा पहुंचे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने सरकार की महिला स्वावलंबन योजना को बढ़ावा देते हुए आम लोगों से भी पिंक ई-रिक्शा का अधिकाधिक उपयोग करने की अपील की। विधानसभा रवाना होने से पहले मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पिंक ई-रिक्शा योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि लोग अधिक से अधिक पिंक ई-रिक्शा का उपयोग करेंगे तो पिंक दीदियों की आय बढ़ेगी और उन्हें स्थायी रोजगार मिलेगा। इधर,विधानसभा का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से भी काफी गर्म रहने के संकेत हैं। कांग्रेस ने बिजली दरों में बढ़ोतरी, महंगाई और चर्चित 'नकटी' प्रकरण सहित कई जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। पार्टी पहले दिन 'नकटी' मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है,जबकि 14 जुलाई को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश करेगी। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव,संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र...राम मंदिर चंदा चोरी पर हंगामा,महेंद्र कर्मा विवि में बीएड-डीएड कोर्स का मुद्दा गूंजा

भूपेश बोले...लोगों ने चंदा दिया,डकैती पड़ गई

रायपुर,13 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत समेत कांग्रेस विधायक चंदा चोरी के पोस्टर लेकर सदन पहुंचे। महंत ने आरोप लगाया कि रामभक्तों की आस्था के साथ धोखा हुआ है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि यह विधानसभा और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। डॉ. रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही पहले पांच मिनट के लिए स्थगित की गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी जारी रही। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था, लेकिन उसमें डकैती पड़ गई। लगातार हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।

स्थगन नामंजूर होने पर हंगामा...

दोनो ओर के विधायकों की ओर से आ रहे अपने-अपने तर्कों के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। स्थगन नामंजूर होन के बाद विपक्ष की ओर से जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। नारेबाजी के बीच भी दोनों पक्षों के बीच राम मंदिर में चोरी पर तीखी बहस होती रही।

कौशिक ने बघेल से पूछा...कितना दिया दान

धरमलाल कौशिक ने भूपेश बघेल से पूछा आपने कितना दान दिया। इस पर श्री बघेल ने सदन जानकारी देते हुए बताया कि,उन्होंने श्रीराम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या को 1 लाख 21 हजार की राशि दान की है। इस बीच भारी हंगामे जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद भी विपक्ष की ओर से नारेबाजी जारी रही। इस बीच भारी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

प्रश्नकाल में डीएड-बीएड कॉलेज का मुद्दा गूंजा

इससे पहले प्रश्नकाल में भाजपा विधायक लता उसेंडी ने कोंडागांव स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में बीएड-डीएड पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने और रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल किया। जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू है। बीएड-डीएड कॉलेजों को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और 13 महाविद्यालयों में इन्हें शुरू करने की संभावना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई को विधानसभा में दी भावभीनी श्रद्धांजलि

छत्तीसगढ़ विधानसभा के पावस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्म विभूषण से सम्मानित विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। निधन उल्लेख के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डॉ. तीजन बाई के निधन से छत्तीसगढ़ ने अपनी लोकसंस्कृति का एक अनमोल रत्न खो दिया है। उनके जाने से कला एवं सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने पंडवानी गायन की कापालिक शैली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपनी विलक्षण प्रतिभा से लोककला को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनकी प्रस्तुतियों में गायन और अभिनय का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था। पात्रों का सजीव चित्रण,ओजपूर्ण वाणी और प्रभावशाली प्रस्तुति श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डॉ. तीजन बाई का जीवन संघर्ष,साधना और समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। जिस दौर में महिलाओं की पंडवानी गायन में भागीदारी अत्यंत सीमित थी,उस समय उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपनी अलग पहचान बनाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनीं। उन्होंने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने एशिया, यूरोप सहित विश्व के अनेक देशों में अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण,संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया।

जेल से छूटते ही बदला लेने पहुंचे बदमाश की हत्या

दुर्ग,13 जुलाई 2026। जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के कुंद्रापारा इलाके में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जेल से छूटने के बाद बदला लेने पहुंचे आदतन बदमाश लेखराम कोठारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पहले से चल रहा था दोनों पक्षों में विवाद : पुलिस के अनुसार, लेखराम कोठारी और चेलक पक्ष के लोगों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच पहले भी मारपीट की घटना सामने आई थी। विवाद बढ़ने के बाद मामला पद्मनाभपुर थाने तक पहुंचा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लेखराम कोठारी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की थी और उसे जेल भेज दिया गया था।

जेल से बाहर आते ही पहुंचा बदला लेने : बताया जा रहा है कि रविवार को जेल से रिहा होने के बाद लेखराम कोठारी अपने कुछ साथियों के साथ चेलक पक्ष के लोगों के पास पहुंच गया। आरोप है कि वह पुराने विवाद का बदला लेने की नीयत से वहां गया था। इसी दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।

घेरकर की गई पिटाई,इलाज के दौरान मौत : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि दूसरे पक्ष के कई लोगों ने लेखराम को घेर लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में लेखराम को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं, इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कुछ अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। हत्या की सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के निजीकरण के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान,22 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में होगा प्रदर्शन

रायपुर,13 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण,आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है। संघ की प्रांतीय महासमिति एवं कोर कमेटी की बैठक में कर्मचारियों के लंबित वेतनमान, नियमित भर्ती,संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन सहित विभिन्न कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई। आंदोलन के प्रथम चरण में 22 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यालय में प्रांताध्यक्ष अनिल पाण्डेय की अध्यक्षता एवं संरक्षक/सलाहकार ओ.पी. शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण की बढ़ती प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में विशेष रूप से पैथोलॉजी और फार्मेसी सेवाओं को एचएलएल कंपनी को सौंपे जाने के बाद भविष्य में व्यापक निजीकरण की आशंका जताते हुए इसका पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि दूसरे राज्यों के डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों के लिए पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त किए जाने से प्रदेश के युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे। साथ ही फर्जी डिग्री और डिप्लोमा धारकों के स्वास्थ्य सेवाओं में प्रवेश की आशंका भी बढ़ेगी,जिससे गुणवत्तापूर्ण उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। महासमिति ने राज्य शासन से स्वास्थ्य कर्मचारियों के लंबित पुनरीक्षित वेतनमान को तत्काल लागू करने,विभाग में स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित भर्ती शुरू करने,संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने,जीवन दीप कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नीति बनाने तथा प्रदेश में स्वास्थ्य आयोग के गठन की मांग की। बैठक में कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के संयोजक अनिल शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में अलग-अलग माध्यमों से निजीकरण की शुरुआत की जा रही है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)